



रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर छत्तीसगढ़



मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य तेजी से तकनीकी नवाचार, आधुनिक उद्योगों और रणनीतिक क्षेत्रों का नया केंद्र बन रहा है। रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए लागू विशेष प्रोत्साहन नीति राज्य को नई पहचान और अपार संभावनाओं की ओर ले जा रही है।

छत्तीसगढ़ का नया विजन

युवा बनेगा परिवर्तन की शक्ति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सोच है कि छत्तीसगढ़ का युवा केवल रोजगार तलाशने वाला न रहे, बल्कि उद्योग और स्टार्टअप स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने वाला बने। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में आधुनिक उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ रही है। इससे छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़ते हुए हाईटेक मैनुफैक्चरिंग और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है।

रक्षा, एयरोस्पेस और स्पेस उद्योगों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज

- ✓ स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर कर लाभ और पूंजी अनुदान
- ✓ ब्याज अनुदान, बिजली शुल्क में छूट और भूमि संबंधी सुविधाएं
- ✓ स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) शुल्क में रियायत
- ✓ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन राशि
- ✓ बड़े निवेश करने वाली इकाइयों को अतिरिक्त औद्योगिक लाभ

स्पेस टेक्नोलॉजी से राज्य को व्यापक लाभ

- कृषि क्षेत्र में सटीक फसल पूर्वानुमान, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार और जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन
- बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली और त्वरित प्रतिक्रिया
- नगर नियोजन, परिवहन व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में स्पेस डेटा का उपयोग
- वन क्षेत्रों की निगरानी और अवैध कटाई की रोकथाम के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग
- पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी सहायता



स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और अनुसंधान को प्राथमिकता

नई नीति में स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार देने वाली इकाइयों को विशेष सहायता दी जा रही है। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान और अत्याधुनिक तकनीकी परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।



स्थायी रोजगार



अनुसंधान और नवाचार



कौशल विकास



स्टार्टअप प्रोत्साहन

इसरो के साथ साझेदारी से विकास को नई गति

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग को नई दिशा मिली है।

- सेटेलाइट आधारित सर्वेक्षण और भू-मानचित्रण
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन
- स्मार्ट कृषि और जल प्रबंधन को बढ़ावा
- आपदा प्रबंधन के लिए आधुनिक चेतावनी प्रणाली
- डेटा विश्लेषण और जीआईएस तकनीक का उपयोग



अनुसंधान संस्थानों और युवाओं को नया मंच

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस पहल से जोड़ा है। इससे हजारों छात्र, शोधकर्ता और युवा वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचारों में योगदान देकर राज्य के विकास में भागीदार बन रहे हैं। यह सहयोग छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और भविष्य के अनुरूप बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।



उद्योग और निवेश : नई ऊंचाइयों की ओर

रक्षा, एयरोस्पेस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों की रुचि लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य में निवेश के नए अवसर बन रहे हैं, औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं और हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यह नीति 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को छत्तीसगढ़ में मजबूत कर रही है।



श्रमिक कल्याण : सरकार की संवेदनशील और समर्पित पहल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के जरिये लाखों श्रमिक परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, मातृत्व सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है - हर श्रमिक सम्मानित हो, सुरक्षित हो और आत्मनिर्भर बने।

सरकार का संकल्प

काम, सम्मान और सुरक्षा हर श्रमिक का अधिकार

- ✓ हर हाथ को काम का अवसर
- ✓ मेहनत का उचित सम्मान
- ✓ हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा
- ✓ बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर
- ✓ भोजन और आवास की सुविधा

मोबाइल कैंप से पंजीकरण अभियान को मिली गति

असंगठित श्रमिकों और निर्माण कर्मचारियों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए राज्यभर में मोबाइल कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक हजारों कैंप आयोजित किए गए, जिनसे बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ और वे योजनाओं से जुड़ सके।



श्रमिक परिवारों के लिए प्रमुख योजनाएं

- ✓ मुख्यमंत्री नौविहाल छात्रवृत्ति योजना
- ✓ मिनीमाता महतारी जतन योजना
- ✓ मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना
- ✓ मुख्यमंत्री नौनी बाबु मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- ✓ निःशुल्क गणवेश एवं अध्ययन सामग्री सहायता योजना
- ✓ उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
- ✓ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
- ✓ शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना

श्रम अन्न योजना का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा संचालित श्रम अन्न योजना प्रदेश के अनेक जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। यह योजना हजारों श्रमिकों को रियायती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रही है।



संवाद-48873/1

नया छत्तीसगढ़, नई पहचान

- ✓ उच्च तकनीक, नवाचार और निवेश का केंद्र
- ✓ युवाओं के लिए रोजगार और करियर के अपार अवसर
- ✓ कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में तकनीकी क्रांति
- ✓ श्रमिकों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध सरकार
- ✓ विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर कदम



छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, तकनीक और संवेदना के साथ - विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर...

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष बने निर्मल

रायपुर। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी के बाद निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड में प्रशांत किशोर को अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। निर्मल कोसरे के सामने अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने और विभाग की गतिविधियों को मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। अनुसूचित जाति विभाग की जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है, जब कांग्रेस प्रदेश में संगठन को अलग-अलग मोर्चों पर सक्रिय करने की तैयारी में जुटी है।

ग्रामीण इलाको में 45 नहीं अब 25 दिन में बुक होगा गैस सिलेंडर

रायपुर। रायपुर समेत प्रदेशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अब यहां के उपभोक्ता भी शहरी क्षेत्र की तरह 45 दिन की जगह 25 दिन में ही गैस सिलेंडर बुक करा सकेंगे। लेकिन अब भी नए कनेक्शन लेने पर रोक लगी हुई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लाखों उपभोक्ताओं का गैस कनेक्शन हैं इसमें दो से तीन हजार सिलेंडरों की बुकिंग प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों से ही होती है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुकिंग की अवधि 45 दिन निर्धारित थी, जिसे घटाकर अब 25 दिन कम कर दिया गया है। हालांकि बुकिंग की टाइम लाइन कम कर दी गई है, लेकिन अब भी नए कनेक्शन लेने पर रोक लगी हुई है। इसके कारण रायपुर जिले के हजारों लोग अब भी नए कनेक्शन के इंतजार में बैठे हुए हैं। इसमें ज्यादातर बाहर से आए, किराए पर रहने वाले लोग शामिल हैं। रोक के कारण लोग अधिक दाम पर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। एजेंसी वाले भी इसके एवज में 10 किलो वाला सिलेंडर लेने की सलाह दे रहे हैं।

पीडीएस के तहत राशन कार्डधारी 30 सितंबर तक ले सकते है दो माह का चावल

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के सभी 14 हजार 186 उचित मूल्य दुकानों में दो माह सितंबर और अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न आबंटन जारी कर दिया गया है। इन उचित मूल्य दुकानों में से 9,356 (66 प्रतिशत) दुकानों में खाद्यान्न का भंडारण हो गया है तथा राशनकार्डधारियों को उक्त दो माह के चावल वितरण जारी है। राशनकार्डधारी कोई भी उचित मूल्य की दुकानों से दो माह का चावल 30 सितंबर तक ले सकते हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में दो माह के खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण का कार्य प्रचलित है। 08 सितंबर 2026 तक खाद्यान्न 2.62 लाख राशनकार्डधारियों द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया गया है। 30 सितंबर 2026 तक 02 माह का खाद्यान्न वितरण पूर्ण करने हेतु सभी जिलों की निर्देश दिए गए है। राज्य शासन द्वारा दो माह के खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण की नियमित निगरानी/मॉनिटरिंग की जा रही है।

तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका इलाके में नो-एंट्री में घुसे वाहन, चालको पर लगा जुर्माना

रायपुर। शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के लिए समय और मार्ग निर्धारित हैं। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक प्रतिबंधित समय में मुख्य मार्गों और अंदरूनी इलाकों में वाहन लेकर पहुंच रहे थे। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के साथ जाम और सड़क सुरक्षा की समस्या भी पैदा हो रही थी। इसी के तहत तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका इलाके में नो-एंट्री के प्रतिबंधित समय में घुसे 7 भारी मालवाहक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सड़क और फुटपाथ पर खड़े वाहनों को त्रेन और टोइंग वाहनों की मदद से हटाया गया। साथ ही उन्हें दोबारा नियम नहीं तोड़ने की समझाइश दी गई। यातायात पुलिस के मुताबिक, रिंग रोड के अंदरूनी हिस्सों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है। भारी वाहनों को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी समय इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।

महासमुंद्र जिले में 6 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 25.67 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने महासमुंद्र जिले की 6 सिंचाई योजनाओं के सुदृढ़ीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ 67 लाख 92 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कक्ष, रायपुर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इन सभी योजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र के कुल 817 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा (डूमरपाली एनीकट निर्माण (सरायपाली) - कटंगी नाला ग्रामीक डूमरपाली एनीकट निर्माण के लिए 3.52 करोड़ से अधिक (3,52,99,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, इससे 100 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। राजाडोरा जलाशय (गिथींग) के नहर के सुदृढ़ीकरण एवं लाईनिंग कार्य के लिए 4.95 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है, इससे 76 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी पहुंचेगा। कुन्ती नाला व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य, नहर के जीर्णोद्धार एवं सी.सी. लाईनिंग के लिए 4.74 करोड़ (4,74,31,000 रुपये) स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 170 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

राजधानी/छत्तीसगढ़

सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रभारी मंत्री नेताम ने ली वर्चुअल बैठक

17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक जिले में होंगे जनभागीदारी के विविध आयोजन

रायपुर। जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर आज वर्चुअल बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली और सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, पूर्व संसदीय सचिव एवं जिला अध्यक्ष चम्पा देवी पावले, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव, जिला पंचायत सदस्य उजित नारायण, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा खलखो सहित समस्त एसडीएम, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं संबंधित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सेवा



संकल्प अभियान के तहत 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी लेते हुए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर तक अभियान को व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य सेवा, सहभागिता और जनभागीदारी को मजबूत करते हुए अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रमों से जोड़ना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम आयोजित करने तथा सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों के दौरान अलग से समन्वय बनाकर कार्यक्रमों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने जिले

में अभियान के अंतर्गत को जा रही तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितम्बर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत जमीनी स्तर पर तथा हर घर में दीप प्रज्वलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसी क्रम में 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नमो सेवा गाथा के अंतर्गत नुक़्कड़ नाटकों का आयोजन ग्राम, नगर एवं विभिन्न संस्थानों में किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनसेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश आमजन तक पहुंचाया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि 25 सितम्बर को आंगन का उत्सव कार्यक्रम जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जाएगा।

जांच में मिला दिल में छेद, बिना ओपन हार्ट सर्जरी के हुआ इलाज

रायपुर। जैकूदर की 8 वर्षीय स्वर्णि बाई जशपुर के छोटे से गांव जैकूदर की 8 वर्षीय स्वर्णि बाई अब सामान्य जिंदगी की ओर लौट रही है। कभी बार-बार छाती में संक्रमण, सांस लेने में तकलीफ और तेज धड़कन से परेशान रहने वाली स्वर्णि के दिल में जन्मजात विकार का पता चला। समय पर जांच और उचित रेफरल के बाद रायपुर में उसका बिना ओपन हार्ट सर्जरी के सफल उपचार किया गया।

दुलदुला विकासखंड के जैकूदर गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली स्वर्णि

को लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) अंतर्गत बच्चे की स्वास्थ्य जांच में हृदय संबंधी रोग का पता चला। जांच में उसके हृदय में बड़े आकार का टाइप-एक पीडीए (मरीज की धमनी वाहीनी) पाया गया।

पीडीए का आकार करीब 5.4 मिलीमीटर था और हृदय में रक्त का असामान्य प्रवाह हो रहा था। विशेषज्ञ उपचार के लिए उसे रायपुर स्थित निजी अस्पताल रेफर किया गया।

छग के तोमन व जम्मू-कश्मीर की शीतल की जोड़ी ने तीरंदाजी में हासिल किया कांस्य पदक

■ शीतल देवी ने व्यक्तिगत राउंड में हासिल किया स्वर्ण पदक

रायपुर। विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरा चरण जो कि अहमदाबादके साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तोमन कुमार और जम्मू-कश्मीर की शीतल देवी की कंपाउंड मिक्स्ड टीम जोड़ी ने बुधवार को इराक की सारा अल-हामीद और अब्बास काज़िम की जोड़ी के खिलाफ खेलते हुए कांस्य पदक हासिल किया।

वहीं शीतल देवी ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की खिलाड़ी ऐज़ादा सेइदान को बुधवार को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उक्त जानकारी



छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के महासचिव आनुष मुरारका ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले तोमन कुमार तोमन कुमार ने मेन्स कंपाउंड टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने साथी श्याम सुंदर स्वामी के साथ मिलकर स्वर्ण पदक पहले ही अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में इराक की जोड़ी को 152-139 से हराया। इसके अलावा वे व्यक्तिगत कैटेगरी में

भी कांस्य पदक के लिए मुकाबला कर रहे हैं। बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की नंबर-1 पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने इसी चैंपियनशिप में एक और इतिहास रचा है। उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन राउंड में 1400/1440 अंकों का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो उनके पेरिस पैरालंपिक के 1399 अंकों के रिकॉर्ड से बेहतर है।

हड़ताल के ऐलान के बाद बस संचालकों की मंत्री केदार कश्यप के साथ बैठक

रायपुर। किराए में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच फेडरेशन पदाधिकारियों और बस संचालकों की बुधवार को मंत्री केदार कश्यप के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सहित परिवहन क्षेत्र से जुड़े की विषयों पर चर्चा की गई।

परिवहन मंत्री कश्यप ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई प्रत्येक मांग और व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बस संचालकों की समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाए। यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

बैठक में फेडरेशन ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग रखी। इसके साथ ही 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का विषय भी मंत्री के समक्ष रखा गया।

परिवहन मंत्री कश्यप ने प्रतिनिधियों को आश्स्त किया कि



यात्री किराए से जुड़े विषय का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी करते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फेडरेशन ने स्लीपर बसों में एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लेने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक स्लीपर पर एक सीट के बराबर टैक्स निर्धारित करने की मांग रखी। बस संचालकों ने इस व्यवस्था से होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी भी मंत्री को दी।

मंत्री कश्यप ने कहा कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को इसके व्यावहारिक, तकनीकी और राजस्व संबंधी सभी पहलुओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

स्टेज कैरिज बसों के बीच समय-अंतराल निर्धारित करने के विषय पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। फेडरेशन

ने मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट और ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतर निर्धारित करने का सुझाव दिया।

परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों को समय-सारिणी ऐसी होनी चाहिए, जिससे यात्रियों को पर्याप्त सुविधा मिले और बस संचालकों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी उत्पन्न न हो। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और बसों के सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया।

बैठक में स्टेज कैरिज वाली सभी यात्री बसों के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परमिट जारी करने की सुविधा का विषय भी रखा गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी बसों के लिए ऑनलाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। परिवहन मंत्री कश्यप ने परमिट सहित परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाए, ताकि बस संचालकों एवं आम नागरिकों को विभागीय कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चकर न लगाने पड़ें।

रायपुर। खरतरगच्छाधिपति आचार्य श्री जिनमणिप्रभ सूरिश्वर जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर में भक्तों ने सीमंधर स्वामी से मोक्ष मार्ग की पुकार लगाई । श्री सीमंधर स्वामी जैन मंदिर व दादाबाड़ी ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष बैद व महासचिव महेन्द्र कोचर ने बताया कि आज रात्रि 8 बजे से श्री सीमंधर स्वामी परमात्मा के सम्मुख भैरव भक्त मण्डल ने सीमंधर स्वामी के पास हमें जाना है , संयम ले के केवल पा के मोक्ष हमें जाना है भावपूर्ण के गीत के माध्यम से श्रद्धालुओं को महाविदेह की भाव यात्रा कर दी। कोचर ने आगे बताया कि श्री सीमंधर स्वामी वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं हम सभी के



लिए मोक्ष जाने का मार्ग हैं । परमात्मा व दादागुरुदेव की प्रतिमाओं की नयनाभिराम आंगी बनाई गई । जिसके दर्शन करने भक्तों का तांता लगा रहा । ट्रस्टी नीलेश गोलछा व डॉ योगेश बंगानी ने बताया कि 11 सितम्बर को प्रभु भक्ति के साथ ही भगवान महावीर स्वामी की माता रानी द्वारा देखे गए 14 महास्वप्नों के पूजन का अवसर श्रद्धालुओं को मिलेगा।

सीजीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जिला प्रशासन की बड़ी पहल

12-13 सितंबर को होगा नि:शुल्क मॉक इंटरव्यू

रायपुर। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साक्षात्कार की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए जिला प्रशासन रायपुर की ओर से ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ के तहत नि:शुल्क मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 12 और 13 सितंबर 2026 को नेतृत्व साधना केंद्र, फुंडडर में होगा।

मॉक इंटरव्यू का उद्देश्य अभ्यर्थियों को वास्तविक साक्षात्कार का अनुभव देना है, ताकि वे परीक्षा के अंतिम चरण के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयार हो सकें। इस दौरान अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की प्रक्रिया, पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के प्रभावी उत्तर देने, व्यक्तिव प्रस्तुतीकरण, आत्मविश्वास और संवाद कौशल से जुड़े जरूरी मार्गदर्शन दिए जाएंगे।

मॉक इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को विशेषज्ञों के समक्ष साक्षात्कार का



अभ्यास करने का अवसर मिलेगा।

उनके प्रदर्शन का आकलन कर आवश्यक सुझाव और फीडबैक भी दिया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों को अपनी कमियों को समझने और वास्तविक साक्षात्कार से पहले उनमें सुधार करने में मदद मिलेगी।

इस अवसर का लाभ लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 11 सितंबर 2026 तक निर्धारित गूगल सीट में अपनी आवश्यक जानकारी भरकर पंजीयन करा सकते हैं। जिला प्रशासन ने सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के

रंगोली राष्ट्र कार्यक्रम के तहत हर घर तथा चर्चनित नगरों में रंगोली बनाई जाएगी। राष्ट्रीय इनोवेशन चौलैंज के अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अभियान के समापन अवसर पर 17 अक्टूबर को जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यक्रमों को ग्राम स्तर से जिला स्तर तक व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान लेखन, भाषण, नाटक, सफलता की कहानी, सेवा ज्योति, स्वच्छता अभियान, जिला स्तरीय कार्यक्रम, समिति सदस्यों की सहभागिता, जिले की कार्यशाला तथा मंडल स्तर की कार्यशाला सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने स्तर पर कार्यक्रमों की तैयारी समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अभियान को जनभागीदारी और आपसी समन्वय के साथ सफल बनाने पर विशेष जोर देते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

महावीर जन्मवांचन के साथ ही पालना जी पूजन भी होगा। पालना जी की भक्ति 12 सितंबर को होगी। भैरव भक्त मण्डल के सुप्रसिद्ध भजन गायक राहुल कोचर अरुण बरलोटा आशीष पारख दीपाली बरलोटा मधु पारख ने मेरे दादा की मूर्ति ऐसे चमके जैसे चमके हीरे मोती मेरे दादा की मूर्ति , ओ पालनहारे निर्गुण ओर न्यारे तुमरे बिन हमरा कोई नही भावपूर्ण भजनों से जनमानस को भावविभोर कर दिया . प्रभुभक्ति के लाभार्थी राजेश जी करुणा जी सिंधी हैं। 10 सितम्बर को वर्द्धमान बहु मण्डल में शताब्दी ढ़ेलडिया व ऐषणा ढ़ेलडिया माँ बेटी की भजन जुगलबंदी की प्रस्तुति होगी।

महावीर जन्मवांचन के साथ ही पालना जी पूजन भी होगा। पालना जी की भक्ति 12 सितंबर को होगी। भैरव भक्त मण्डल के सुप्रसिद्ध भजन गायक राहुल कोचर अरुण बरलोटा आशीष पारख दीपाली बरलोटा मधु पारख ने मेरे दादा की मूर्ति ऐसे चमके जैसे चमके हीरे मोती मेरे दादा की मूर्ति , ओ पालनहारे निर्गुण ओर न्यारे तुमरे बिन हमरा कोई नही भावपूर्ण भजनों से जनमानस को भावविभोर कर दिया . प्रभुभक्ति के लाभार्थी राजेश जी करुणा जी सिंधी हैं। 10 सितम्बर को वर्द्धमान बहु मण्डल में शताब्दी ढ़ेलडिया व ऐषणा ढ़ेलडिया माँ बेटी की भजन जुगलबंदी की प्रस्तुति होगी।

अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है। पंजीयन अथवा आयोजन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी रोजगार अधिकारी केदार पटेल (9425502970) और चंद्रेश (7389931878) से संपर्क कर सकते हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए विभिन्न नवाचारी पहल की जा रही हैं। ‘प्रोजेक्ट अनुभव’ भी इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसके माध्यम से सीजीपीएससी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार चरण की व्यावहारिक तैयारी का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, (वि./ यां.) संभाग कांकेर			
निविदा आमंत्रण सूचना			
ज्ञाप क्र.- 1788 / NIT-27/व.ले./2026-27	निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	कांकेर, दिनांक 07/09/2026	
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	16/09/2026 अपराह्न 5.30 बजे तक	
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	24/09/2026 अपराह्न 5.30 बजे तक	
निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि	25/09/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक	
एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है-			
एनआईटी क्र. निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) अमानत राशि (रु. में) बैंक सालवेंसी (रु. में)	
1	2	3	
NIT-27 To036	लो.नि.वि. वि./यां उपसंभाग कांकेर अंतर्गत विभिन्न आवासीय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	8. 00 6000.00 120000.00	
NIT-27 To037	लो.नि.वि. वि/या उपसंभाग कांकेर अंतर्गत जिला प्रशासन के आवासीय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	8.00 6000.00 120000.00	
NIT-27 To038	लो.नि.वि. वि./यां. उपसंभाग काकेर अंतर्गत न्याय प्रशासन के आवासीय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	4.00 4000.00 60000.00	
NIT-27 To039	लो.नि.वि. वि./यां उपसंभाग काकेर के सिविल संभाग भातुप्रतापपुर अर्गत गैर आवासीय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	8.00 6000.00 120000.00	
NIT-27 To040	लो.नि.वि.वि./यां. उपसंभाग काकेर के सिविल संभाग कांकेर अंतर्गत गैर आवासीय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	9.00 6750.00 135000.00	
NIT-27 To041	लो.नि.वि. वि./यां. उपसंभाग कांकेर अंतर्गत विभिन्न राजकीय उच्चतर विद्यालय व महाविद्यालय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	8.00 6000.00 120000.00	
NIT-27 To042	लो.नि.वि. वि./या. उपसभाग काकेर अतर्गत विभिन्न माध्यमिक विद्यालय भवनों में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	9.00 6750.00 135000.00	
NIT-27 To043	लो.नि.वि. वि./या. उपसंभाग कांकेर अंतर्गत विश्राम गृह एवं विश्राम भवन में वार्षिक विद्युत मरम्मत कार्य। प्रथम आमंत्रण	8.00 6000.00 120000.00	
नोट:-			
1) प्रत्येक निविदा हेतु निविदाकर्ता की श्रेणी ई पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी "द" से "अ" तक ।			
2) प्रत्येक निविदा हेतु कार्य की अवधि दिनांक 31/03/2026 तक होगी, वर्षा ऋतु सहित।			
3) प्रत्येक कार्य हेतु निविदा प्रपत्र की कीमत रु. 750/- एवं निविदा प्रपत्र का प्रकार 'अ'।			
4) अमानत राशि हेतु प्रस्तुत FDR/TDR में फर्म का नाम एवं कार्यालयन अभियंता, लो.नि.वि. (वि./यां) संभाग कांकेर के नाम से जारी होना चाहिए।			
निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाइट www.pwd.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं।			
इन्का अवलोकन संबंधित संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।			
कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, (वि./यां.) संभाग कांकेर (छ.ग.)			
जी-262703163/5			

मोदी@25 : जब भारत हो जाएगा ‘मोदीमय’

हरीश गुप्ता

अगले 15 दिनों तक भारत की राजनीति में एक ही विषय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है- ‘नरेंद्र मोदी@25’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवैधानिक पद पर 25 वर्ष पूरे होने के मौके को यादगार बनाने के लिए भाजपा और उसकी सरकारें राष्ट्रीय स्तर पर जश्न की तैयारियां कर रही हैं। इस अवसर को हर साल होने वाले ‘सेवा पखवाड़े’ के तहत 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। इस बार इसका आयोजन बहुत बड़े स्तर पर किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर गांधी जीयंती तक चलने वाला यह पखवाड़ा मोदी की राजनीतिक यात्रा पर केंद्रित होगा-2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 से लगातार प्रधानमंत्री रहने तक। तैयारियां काफी व्यापक हैं। भाजपा ने सेवा से जुड़े 13 बड़े कार्यक्रम तय किए हैं। इनमें रकदान शिविर, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जल योजनाएं और दूसरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही बौद्धिक और प्रचार अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। सेमिनार, प्रदर्शनियां और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए मोदी की राजनीतिक यात्रा को सुशासन, जनकल्याण और विकास के नजरिए से प्रस्तुत किया जाएगा। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम-किसान, यूपीआई जैसी उन प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख होगा, जिनका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा है। आर्थिक उपलब्धियों को भी इस अभियान में प्रमुखता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7।8 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। इसे भी मोदी सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया जाएगा। इस जश्न का दायरा देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। विदेशी नेताओं के संदेश और शुभकामनाएं भी इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय रंग देंगी। कुल मिलाकर यह 15 दिनों का एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन होगा-मैदान में सेवा कार्य, पदें पर उपलब्धियों का प्रदर्शन और केंद्र में नरेंद्र मोदी। ऐसे में पूरा देश कुछ समय के लिए और ज्यादा ‘मोदीमय’ दिखाई दे सकता है।

राज्यसभा के लिए स्मृति ईरानी की दावेदारी! भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को टीम में शामिल आठ महासचिवों में से दो आगामी नवंबर में होने वाले राज्यसभा चुनाव में जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं के मुताबिक स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राज्यसभा के लिए नामांकन की उम्मीद लगाए हुए हैं। माना जा रहा है कि भाजपा 10 में से 8 राज्यसभा सीटें जीत सकती है। स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार गई थीं। इसके बाद वह कुछ समय तक सक्रिय राजनीति में ज्यादा नजर नहीं आई। पिछले महीने उन्हें भाजपा का महासचिव बनाकर फिर से महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। राज्यसभा के एक और संभावित दावेदार हरीश द्विवेदी हैं, जो 2024 में बस्ती लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। भाजपा नेतृत्व का उन पर काफी भरोसा बताया जाता है। भाजपा के बाकी महासचिव-विनोद तावड़े, बिप्लव कुमार देब, सतीश पूनिया, गणेश पटेल और संजय भाटिया-पहले से ही सांसद हैं। सुनील बंसल अकेले ऐसे महासचिव हैं, जिनकी सांसद बनने में कोई दिलचस्पी नहीं बताई जाती। बी।एल। संतोष की तरह आरएसएस से भाजपा में आए बंसल संगठन में ही काम करते रहना चाहते हैं। एक समय उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली भाजपा नेताओं में गिना जाता था। चर्चा है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में आठ में से कम से कम छह नए चेहरे हो सकते हैं।

पुराण दिग्दर्शन

विश्व विद्या-निरुपणाध्याय: (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

प० शिवशङ्कर मिश्र की राय

जैनधर्म और बौद्धधर्म को मिटाने में इन पुराणों ने बड़ा प्रभाव विखाया । इस पुराणों के प्रताप से हिन्दुधर्म डूबता 2 बचा, साथ ही

एक यह बात भी स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि पुराणों द्वारा देश में भक्तिरस का कुछ विलक्षण रस फैल गया, साथ ही पांच देवताओं की उपासना आदि का प्रभाव खूब बढ़ा। इनके प्रसार के कारण उस समय प्रतियोगिता में जैनधर्म टिक न सका और हिन्दू धर्म ने अपना सिक्का फिर जमा लिया ।

(भारत का धार्मिक इतिहास पृष्ठ 153 से-)

बस हम इन्हीं शब्दों के साथ करुणावरुणालय पुराण-पुरुष परमात्मा को अनन्त प्रणाम करते हुए इस ग्रन्थ को यहीं समाप्त करते हैं। श्रीराम् !

सब विद्या सब कला ज्ञान, विज्ञान तत्त्व के सिन्धु पुराण।



यही रात्र अध्याय दशम का, श्री भगवान् करें कल्याण ।।
दसवां अध्याय समाप्त
नह्यत्र किंचिदवि नूतनमिति प्रवाद:,
पौराणिकस्य मम भूषणमेव लोके ।
पूज्ये पुराणं-पुरुषेऽनवताप्रसङ्ग:,
नारायणस्य किमु! लाघवतां व्यतिक्रि ।।



कालिलाल मांडेर

वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेन-जी के बीच पहुंचना भारतीय राजनीति में बदलते संवाद की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। मंच तक पहुंचने के लिए बनाया गया रैंप, लोकप्रिय संगीत की धुनों के बीच युवाओं के बीच पहुंचते प्रधानमंत्री और मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें बनाते युवा—यह दृश्य किसी पारंपरिक राजनीतिक सभा से अलग था। लेकिन इस पूरे आयोजन का महत्व केवल इसकी प्रस्तुति में नहीं है। इसके पीछे भारतीय राजनीति की वह बदलती जरूरत दिखाई देती है, जिसमें नई पीढ़ी को केवल मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में देखा जा रहा है।

वडोदरा में करीब छह हजार युवाओं की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का लगभग 25 मिनट का संवाद इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर संकेत करता है। प्रधानमंत्री ने युवाओं की विकास की यात्रा से जोड़ने की कोशिश की और साथ ही उन्हें झूठे दावों तथा भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का संदेश दिया। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह संदेश विपक्ष पर निशाना साधने का माध्यम भी बना। खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस के युवा एवं छत्र संवाद अभियानों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री की टिप्पणी को राजनीतिक तंज के रूप में देखा गया। मगर इस बयान का एक बड़ा सामाजिक संदर्भ भी है। डिजिटल युग में युवा जिस सूचना संसार में रह रहा है, वहां सच और प्रचार के बीच अंतर करना पहले से कठिन हो गया है।

भारतीय राजनीति में लंबे समय तक जनसभा का अर्थ था मंच, माइक, भाषण और तालियां। नेता बोलता था और जनता सुनती थी। सोशल मीडिया और डिजिटल संचार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। आज युवा नेता का भाषण सुनने के बजाय उसके छोटे वीडियो देखता है, उसके वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देता है और उसी समय अपनी राय भी सार्वजनिक कर सकता है। राजनीतिक दलों को अब केवल सभा आयोजित करने से संतुष्टि नहीं मिल सकती। उन्हें यह समझना पड़ रहा है कि युवा किस भाषा में बात सुनना चाहता है और किस माध्यम से राजनीतिक संदेश उसके पास पहुंच सकता है।

वडोदरा का आयोजन इसी बदलाव का उदाहरण रहा। प्रधानमंत्री का रैंप पर चलकर युवाओं के बीच पहुंचना प्रतीकात्मक रूप से उस

ज्ञान/मीमांसा

रैंप से युवाओं तक पहुंची राजनीति



दूरी को कम करने की कोशिश थी जो आमतौर पर बड़े मंच और दर्शकों के बीच होती है। लोकप्रिय गीतों का इस्तेमाल भी यह बताता है कि राजनीतिक आयोजनों की प्रस्तुति में मनोरंजन और युवाओं की सांस्कृतिक पसंद को जगह मिल रही है। राजनीति की भाषा गंभीर रह सकती है, लेकिन उसका माध्यम अब बदल रहा है।

यह बदलाव केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। कांग्रेस भी छात्रों और युवाओं के बीच सीधे संवाद का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी की सोशल मीडिया गतिविधियां और छत्र-केंद्रित कार्यक्रम इस बात के संकेत हैं कि विपक्ष भी नई पीढ़ी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से युवाओं और किशोरों के साथ संवाद कार्यक्रमों पर बढ़ता जोर भी इसी व्यापक बदलाव का हिस्सा है। इसका अर्थ साफ है कि जेन-जी अब भारतीय राजनीति का ऐसा वर्ग है, जिसे कोई भी बड़ा राजनीतिक संगठन नजरअंदाज नहीं कर सकता।

युवाओं की राजनीतिक अहमियत केवल इसलिए नहीं बढ़ी है कि वे सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनकी संख्या भी चुनावी गणित को प्रभावित करने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 22.78 प्रतिशत बताई गई थी। यानी लगभग हर चार मतदाताओं में एक युवा था। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी यह वर्ग राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

गुजरात जैसे राज्यों में युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों युवा मतदाता हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में भी नई पीढ़ी चुनावी समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए राजनीतिक दलों की नजर अब केवल जातीय, क्षेत्रीय या पारंपरिक सामाजिक समीकरणों पर नहीं रह सकती। उन्हें यह भी समझना होगा कि

युवा मतदाता किस मुदे पर मतदान करता है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।

जेन-जी की राजनीतिक सोच को केवल किसी पार्टी के समर्थन या विरोध से समझना भी उचित नहीं होगा। यह पीढ़ी रोजगार चाहती है, लेकिन केवल नौकरी नहीं। वह कौशल और अवसर चाहती है। वह तकनीक को अपनाना चाहती है, लेकिन तकनीकी बदलाव से पैदा होने वाली असुरक्षा को भी समझती है। वह डिजिटल सुविधा चाहती है, लेकिन विश्वसनीय सूचना भी चाहती है। वह देश की प्रगति पर गर्व कर सकती है, लेकिन अपने व्यक्तिगत भविष्य को लेकर ठोस जवाब भी मांगती है।

वडोदरा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा विकास परियोजनाओं को समर्पित था। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण हिस्सों को राह को समर्पित करना, नई रेल सेवाओं की शुरुआत और कई रेल एवं सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास इस बात को रेखांकित करता है कि बुनियादी ढांचा सरकार के विकास मॉडल का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को केवल रेल परियोजना मानना इसके महत्व को छोटा करके देखना होगा। भारत जैसे विशाल देश में माल की तेज आवाजाही उद्योग और व्यापार की रीढ़ है। यदि बंदरगाह से माल औद्योगिक क्षेत्रों और बाजारों तक कम समय में पहुंचता है तो इससे परिवहन लागत घट सकती है और उत्पादन व्यवस्था अधिक कुशल बन सकती है। मालगाड़ियों के लिए अलग मार्ग बनने से यात्री ट्रेनों पर भी दबाव कम करने की संभावना रहती है। प्रधानमंत्री ने इसी बदलाव को समझाते हुए मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से डबल कंटेनर मालगाड़ी के जरिए बड़ी मात्रा में माल पहुंचाने का उदाहरण दिया। उनका तर्क था कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को तेज गति से पहुंचा सके। यह तर्क आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के सामने केवल उत्पादन बढ़ाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उत्पादन को बाजार तक कम लागत और कम समय में पहुंचाने की चुनौती भी है।

लेकिन युवाओं के बीच विकास की बात तभी पूरी होगी जब उसके साथ रोजगार की बात भी उतनी ही मजबूती से होगी। बड़े रेवेन्यू कॉरिडोर, सड़कें, पुल, बंदरगाह और अन्य

बुनियादी ढांचे आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकते हैं। निर्माण के दौरान प्रत्यक्ष रोजगार और परियोजनाओं के पूरे होने के बाद अप्रत्यक्ष अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन जेन-जी इससे आगे की दुनिया देख रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सीमीकंडक्टर, वित्तीय तकनीक और नए उद्योगों के विस्तार के बीच युवाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे इस बदलती अर्थव्यवस्था में अपनी जगह कैसे बनाएंगे। केवल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी। कौशल, तकनीकी समझ और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होगी। इसलिए युवा संवाद को केवल राजनीतिक भाषण तक सीमित रखने के बजाय शिक्षा और रोजगार की नीतियों से जोड़ना जरूरी है।

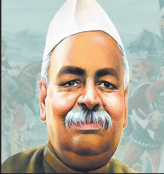
प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने का संदेश आज के समय में विशेष महत्व रखता है। सोशल मीडिया ने सूचना को लोकतांत्रिक जरूर बनाया है, लेकिन इसके साथ गलत सूचना के प्रसार की चुनौती भी बढ़ी है। कोई अधूरा वीडियो, पुरानी तस्वीर या गलत दावा कुछ ही समय में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है।

ऐसे माहौल में युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। किसी भी राजनीतिक दावे को केवल इसलिए सही नहीं मानना चाहिए क्योंकि वह अपने पसंदीदा नेता या संगठन की ओर से आया है। लोकतंत्र में राजनीतिक जागरूकता का अर्थ केवल यह जानना नहीं कि किसे समर्थन देना है, बल्कि यह समझना भी है कि किसी दावे का आधार क्या है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावों को समान कसौटी पर परखने की आदत लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत करती है।

इसलिए प्रधानमंत्री का संदेश यदि राजनीतिक तंज से आगे बढ़कर सूचना-साक्षरता को व्यापक पहल में बदलता है तो उसका महत्व और बढ़ सकता है। युवा जितना तथ्यपरक होगा, राजनीतिक संवाद भी उतना ही स्वस्थ होगा।

जेन-जी को जोड़ने की कोशिश भारतीय राजनीति के लिए नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही है। भाजपा के पास प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और मजबूत डिजिटल पहुंच है। कांग्रेस राहुल गांधी के माध्यम से युवाओं और छात्रों के बीच प्रत्यक्ष संवाद का प्रयास कर रही है। संघ भी अपने सामाजिक और वैचारिक संवाद को नई पीढ़ी तक ले जाने की कोशिश कर रहा है।

पंडित गोविन्द बल्लभ पंत



न्याय और प्रदेश में नियोजित विकास की नींव रखने के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। एक वकील के रूप में आपके बारे में जग जाहिर था कि वह सिर्फ सच्चे केस लेते

थे। वह झुट पर आधारित मुकदमे स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने काकोरी कांड, मेरठ षड्यंत्र के क्रांतिकारियों के अलावा प्रताप समाचार पत्र के सम्पादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के उत्पीड़न के विरोध में अदालतों में प्रभावशाली ढंग से पैरवी की थी। उन्होंने शक्ति नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जिसमें वह कुमार्चू की समस्याओं को उजागर करते थे। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कुली बेगारी प्रथा के विरोध में अभियान चलाया। वह कलम के एक साहसी एवं वीर योद्धा भी थे। उन्होंने अपनी कलम को भी अंग्रेजी शासन को उखाड़

फेंकने के लिए एक सशक्त हथियार बनाया। पंत जी बाद में कुली बेगार कानून के खिलाफ साहसपूर्वक लड़े। कुली बेगार कानून में था कि लोकल लोगों को अंग्रेज अफसरों का सामान फ्री में ढोना होता था। पंत इसके विरोधी थे। पंत जब वकालत करते थे तो एक दिन वह चैबर से गिरीताल भूमने चले गए। वहां पाया कि दो लड़के आपस में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे। यह सुन पंत जी ने युवकों से पूछा कि क्या यहां पर भी देश-समाज को लेकर बहस होती है। इस पर लड़कों ने कहा कि यहां नेतृत्व की जरूरत है। पंत जी ने उसी समय युवाओं की आवाज बनने के संकल्प के साथ से राजनीति में आने का निश्चय कर लिया। वह दिसम्बर 1921 में महात्मा गान्धी के आह्वान पर असहयोग आन्दोलन में शामिल होकर खुली राजनीति में उतर आये।

सऊदी पर हूती अटक होते ही छिप गयी मुनीर की सेना

नीरज कुमार दुबे

मक्का पैकट को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, लेकिन उसकी पहली बड़ी परीक्षा ने ही इस रक्षा समझौते की असली ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब पर हूती मिसालों और ड्रोन की बारिश हुई, दक्षिणी शहरों में नागरिक और आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, ऊर्जा प्रतिष्ठानों में आग लगी और 73 लोग घायल हुए, लेकिन मैदान में दिखाई दी तो सिर्फ निंदा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ पूरी एकजुटता जताई, उसकी संप्रभुता की रक्षा के अधिकार को भी बात सामने आई। कई ऊर्जा प्रतिष्ठानों में आग लगी और कुछ जगहों पर संचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। हूतियों ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उन्होंने अबहा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, किंग खालिद एयर बेस और अरामको से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। रियाद ने इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना उकसावे वाली कार्रवाई बताते हुए जवाब देने की चेतावनी दी है। सऊदी नेतृत्व का कहना है कि देश की संप्रभुता, नागरिकों और राष्ट्रीय संरक्षित्यों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर हूती इन हमलों को यमन में सऊदी समर्थित बलों की कार्रवाई का जवाब बता रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले दिनों यमन के कई इलाकों में 120 से ज्यादा हवाई हमले हुए और एक जेल पर हमले में 11 लोगों की मौत हुई।

यानी यह सिर्फ एकतरफा हमला नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ता प्रतिशोध का चक्र है। यहीं पाकिस्तान पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस्लामाबाद ने कहा कि वह सऊदी अरब की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ खड़ा है। लेकिन क्या निंदा और समर्थन ही उस रक्षा समझौते की पूरी सीमा है, जिसके बारे में सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरोध की बातें की गई थीं? अगर नहीं, तो पाकिस्तान की वास्तविक भूमिका क्या होगी? क्या वह सैन्य सहयोग करेगा, खुफिया सहायता देगा, हवाई सुरक्षा में मदद करेगा या केवल बयान जारी करता रहेगा?



साथ ही सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है।

तुर्किये कहा है? जिस त्रिपक्षीय ढांचे को क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा का माध्यम बताया गया था, उसकी विश्वसनीयता तभी साबित होगी जब संकट के समय उसके सदस्य अपनी प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में बदलें। सवाल उठता है कि अगर संकट के वक्त भी सैन्य गठबंधन केवल बयानबाजी तक सीमित रहे, तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है?

देखा जाये तो खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हूती-सऊदी टकराव अकेला मोर्चा नहीं है। हूती लाल सागर और बाब-अल-मंदेब के आसपास समुद्री यातायात को निशाना बनाने की क्षमता पहले ही दिखा चुके हैं। जुलाई में उन्होंने सऊदी तेल टैंकों पर हमले और रियाद के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की थी। दूसरी तरफ सऊदी समर्थित यमनी बल हूतियों के खिलाफ जवाबी अभियान चला रहे हैं। दक्षिण-पश्चिमी यमन में लड़ाई तेज होने से सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों के विस्थापित होने की खबरें हैं।

सबसे खतरनाक बात यह है कि यह संघर्ष उस समय भड़क रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव अलग मोर्चे पर चल रहा है। एक तरफ फारस की खाड़ी और होर्मुज, दूसरी तरफ लाल सागर और बाब-अल-मंदेब, दोनों समुद्री गलियारों पर संकट एक साथ गहराया तो इसका असर सिर्फ मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। सऊदी ऊर्जा ढांचे पर लगातार हमले वैश्विक तेल बाजार के लिए बड़ा झटका बन सकते हैं। शुरुआती हमलों के बाद ही कुछ तेज के की कोमर्तों में उछाल दर्ज किया गया है। यदि रिफाइनरी, पाइपलाइन, प्रसंस्करण केंद्र या निर्यात ढांचा लगातार निशाने पर आया तो बाजार में वास्तविक सप्लाई पर असर हो सकता है। इसका असर पेट्रोल-डीजल से लेकर परिवहन, विनिर्माण और महंगाई तक पहुंच सकता है।

भारत के लिए खतरा और सीधा है। खाड़ी से

आज का इतिहास

1823 साइमन बोलिवर पेरु के राष्ट्रपति बने।

1846 एलायस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया।

1847 हवाई द्वीप में पहला थियेटर खुला।

1887 भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत का जन्म।

1914 फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मॉर्न का युद्ध समाप्त।

1926 इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अहरण। विमान को लाहौर ले जाया गया। यात्री और चालक दल के सदस्य सकुशल मुक्त किए गए।

1939 कनाडा ने द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1966 संसद ने पंजाब एवं हरियाणा के गठन को मंजूरी दी।

1974 अफ्रीकी देश गिनी ने पुर्तगाल से स्वतंत्रता हासिल की।

1976 इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अहरण। विमान को लाहौर ले जाया गया। यात्री और चालक दल के सदस्य सकुशल मुक्त किए गए।

1996 संयुक्त राष्ट्र आस सभा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि तीन के मुकाबले 158 मतों से स्वीकृत, भारत सहित तीन देशों द्वारा संधि का विरोध।

1998 येवेगेनी प्रीमाकोव को रूस का नया प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया परमाणु अप्रसार की दिशा में समर्पित प्रयास करने पर सहमत।

2002 यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

2003 विश्व व्यापार संगठन की पांचवी मॉन्स्टरीय बैठक कानकुन में प्रारम्भ।

2007 एक नाटकीय घटनाक्रम में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने के बाद पुनः जेद्दा निर्वासित किया गया।

2008 सर्वोच्च न्यायालय ने उपहार अग्निकांड मामले में दोषी ठहराये गए असल बंधुओं की जमानत रद्द की।

2009 जेट एयरवेज़ प्रबंधन और उसके पायलट व्यापक समझौते पर राजी हुए।

2011 भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग को 21वीं सदी के लिए महत्त्वपूर्ण और अपरिहार्य बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि दोनों देशों के बीच गहरे और व्यापक संबंध हैं, जिनका उद्देश्य एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि कायम करना है।

2016 रियो पैरा ओलंपिक में मरियपपन थंगावेलु ने स्वर्ण पदक और रियो भाटी ने कांस्य पदक जीता।

2020 फ्रांस द्वारा निर्मित बहु भूमिका वाले पांच राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए।

आखिर युवाओं के बीच कयों नहीं चमक पा रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन?

कमलेश पांडे

भाजपा के राजनीतिक गलियारों में एक सवाल सबको बेचैन किए हुए हैं कि आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन युवाओं के बीच क्यों नहीं चमक पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव, आप नेता अरविंद केजरीवाल, जनसुराज नेता प्रशांत किशोर आदि जैसे राजनीतिक क्षेत्रों को सियासी रूप से निपटाने के लिए नितिन नवीन के रूप में जो राजनीतिक तुरूप का पता चला है, वह अब मनहूसियत की ओर अग्रसर है।

कहीं विपक्ष के इशारे पर थिरक रहा जेन-जी भारी पड़ रहा है तो कहीं सर्वण संगठनों का जनप्रदर्शन भाजपा नेतृत्व की रीति-नीति पर सवालों के गोले बरसा रहा है। वहीं कांग्रेस व उसके समर्थक दल जिस तरह से अपने अपने मुद्दों पर भाजपा को घेर रहे हैं, उससे पार्टी के कट्टर समर्थकों में भी ऊहापोह मची हुई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन उनकी उपलब्धि जरूर है, लेकिन सवाल तो यहां तक उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

गृहमंत्री अमित शाह पार्टी की कीमत पर उन्हें एक सीमा के बाद युवाओं के बीच चमकने नहीं देना चाहते और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा की तरह सिर्फ अपना-अपना अनुगामी बनाए रखना चाहते हैं? प्रवासीनेटवर्क जुड़े चूँकि नितिन नवीन के ऊपर पीएम मोदी का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए उनपर एक सीमा के बाद बड़े नेता विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं और अफवाह उड़वा रहे हैं कि नितिन नवीन में नैसर्गिक नेतृत्व क्षमता की कमी है? इससे मोदी-भागवत दोनों परेशान हैं। राजनीतिक विश्लेषक की मानें तो यह सवाल असल में नितिन नवीन की व्यक्तिगत क्षमता से ज्यादा भाजपा के सत्ता-संगठन मॉडल का सवाल है?

अभी उपलब्ध घटनाक्रम को देखकर सीधे यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें युवा कम दिलचस्पी लेते देना चाहते। लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की पर्याप्त जगह मिलती है?

देखा जाए तो अगस्त 2026 में नितिन नवीन ने स्वयं Gen Z outreach की रणनीति पर बड़ी बैठक की, जिसमें



करीब 45 नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी ने युवाओं के मुद्दों और उनसे संवाद की रणनीति पर जोर दिया है, हालांकि सर जमीन पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें युवा कम दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा, मेरे आकलन में तीन संभावनाएँ हैं-

पहली, यह नियंत्रित नेतृत्व की रणनीति हो सकती है- भाजपा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीतिक ब्रांड-शक्ति इतनी बड़ी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वतंत्र जन-नेता के रूप में उभरना आसान नहीं है। पार्टी अध्यक्ष का प्राथमिक

काम संगठन, चुनाव और रणनीति का संचालन रहता है; लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का समानांतर राष्ट्रीय चेहरा बना उसका घोषित उद्देश्य नहीं होता। इसलिए नितिन नवीन की दृश्यता कम होना अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है।

दूसरी, नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय नेता बनने की प्रक्रिया में हैं- वे भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी नई राष्ट्रीय टीम में अनुभव तथा युवा ऊर्जा को मिलाने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और राष्ट्रीय जननेता बनना दो

अलग चीजें हैं। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय जननेता बनने के लिए चाहिए- अपनी विशिष्ट राजनीतिक भाषा, युवाओं के बीच स्वतः आकर्षण, लगातार देशव्यापी उपस्थिति, कठिन मुद्दों पर स्वतंत्र विचार, संगठन से बाहर भी व्यक्तिगत जनाधार, मीडिया और सोशल मीडिया में अपनी पहचान, लेकिन इनमें से अधिकांश का मूल्यांकन अभी करना जल्दी होगा।

तीसरी, सबसे दिलचस्प संभावना: नितिन नवीन की क्षमता है, लेकिन उनका राजनीतिक ब्रांडिंग अभी विकसित नहीं हुई है- यही वह जगह है जहाँ मैं आपको पिछली बात से सहमत हूँ कि युवाओं को जोड़ना केवल कार्यक्रमों से नहीं होगा। पार्टी अभी bike yatras, hackathons, marathons, campus activities और social-media outreach जैसी योजनाओं पर विचार कर रही है। लेकिन युवा किसी नेता से केवल यह नहीं सुनना चाहता कि मोदी सरकार ने यह किया, बल्कि अब वह पूछता है : आप स्वयं मेरे लिए क्या सोचते हैं? यहीं नितिन नवीन को अपनी अलग पहचान बनानी होगी। असली परीक्षा यही है।ऐसे में अगर नितिन नवीन हर भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों

के प्रवक्ता बने रहेंगे, तो वे संगठन के सफल अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन युवा जननेता बनने में कठिनाई होगी। लेकिन यदि वे कहें—मोदी जी ने भारत को 2047 का लक्ष्य दिया है; अब मेरी पीढ़ी तय करेगी कि उस भारत की शिक्षा, रोजगार, एआई, उद्यमिता और राजनीति कैसी होगी। तो एक अलग राजनीतिक आवाज पैदा होगी।

मेरे पास ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि मोदी या शाह नितिन नवीन को युवाओं के बीच उभरने में रोक रहे हैं। उलटे, उपलब्ध रिपोर्टों में मोदी और शाह की ओर से युवाओं को केंद्र में रखने की बात तथा नितिन नवीन के नेतृत्व में तद्वृत् श्रद्धहृद्दुष्पृद्द को आगे बढ़ाने की तस्वीर मिलती है। लेकिन भाजपा की राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का चेहरा जरूर है, वह यह कि - मोदी = सर्वोच्च राष्ट्रीय राजनीतिक ब्रांड। शाह = संगठन/रणनीति का शक्तिशाली केंद्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष = संगठन का चेहरा और समन्वयक। नितिन नवीन को इस ढाँचे के भीतर रहते हुए अपनी जगह बनानी होगी।और अगर प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता की बात करें? तो अभी फैसला देना जल्दबाजी होगा, बल्कि मैं नितिन नवीन के लिए अगले 12ः18 महीने

को नेतृत्व की अग्निपरीक्षा मानूंगा। तब देखना होगा कि क्या वे युवाओं के बीच बिना प्रधानमंत्री के नाम के भी भीड़ आकर्षित कर सकते हैं? बेरोजगारी, परीक्षा, शिक्षा और ङु जैसे असुविधाजनक सवालों पर अपनी भाषा विकसित करते हैं? भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ-साथ नए युवाओं को भी नेतृत्व में ऊपर लाते हैं? सोशल मीडिया पर केवल पार्टी का संदेश दोहराने के बजाय अपना राजनीतिक विचार रखते हैं? किसी संकट में स्वयं आगे आकर समाधान प्रस्तुत करते हैं? राज्यों में जाकर नितिन नवीन मॉडल जैसी कोई संगठनात्मक पहचान बनाते हैं? अगर इन छह सवालों का जवाब अगले डेढ़ साल में ही होता है, तो यह कहना मुश्किल होगा कि उनमें प्राकृतिक नेतृत्व क्षमता नहीं है। वहीं, नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ा खतरा मोदी-शाह से कम और सिर्फ अध्यक्ष रह जाने का ज्यादा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वे सफल हो सकते हैं—बैठकें करें, संगठन विस्तार करें, चुनाव जिताएँ, पदाधिकारी नियुक्त करें। उनकी नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का मिश्रण भी इसी संगठनात्मक भूमिका की ओर संकेत करता है।

मिट्टी के गणेश की स्थापना बने देश का संकल्प

कातिलाल मांडोत

गणेशोत्सव केवल भगवान गणेश की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के साथ जुड़ाव का भी उत्सव है। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के साथ देशभर में लाखों घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना होती है। श्रद्धालु पूरी आस्था और उत्साह के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं और उत्सव के समापन पर प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ इस धार्मिक परंपरा के सामने पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी चुनौती भी खड़ी हुई है। यही कारण है कि अब गणेशोत्सव को ऐसी दिशा देने की जरूरत है, जिसमें आस्था भी बनी रहे और प्रकृति की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।

गणेशोत्सव का आगाज होने वाला है और ऐसे समय में पूरे देश को एक ऐसा संकल्प लेने की जरूरत है, जो अपने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। यह संकल्प मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की स्थापना का होना चाहिए। यदि घर-घर और सार्वजनिक आयोजनों में मिट्टी के गणेश को प्राथमिकता दी जाए तो धार्मिक आस्था के साथ जल, मिट्टी और जलीय जीवों की रक्षा का संदेश भी मजबूत होगा। गणेशजी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और अगर सबसे बड़ा विघ्न प्रदूषण का बढ़ता संकट है। ऐसे में पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा की स्थापना वास्तव में प्रकृति की रक्षा की दिशा में एक सार्थक धार्मिक पहल बन सकती है।

हाल ही में धरमपुर में आयोजित इको फ्रेंडली गणेश मेकिंग वर्कशॉप ने इसी सोच को जमीन पर उतारने का सुंदर प्रयास किया। लेडी विल्सन म्यूजियम और धरमपुर नगर पालिका संचालित एएसएमएसएन बाल लाइब्रेरी के संयुक्त आयोजन में बच्चों और नागरिकों ने प्राकृतिक मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाई। करीब 85 प्रतिभागियों की भागीदारी यह बताती है कि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और यदि बच्चों तथा नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाई जाए तो वे परंपरा और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इस तरह के आयोजन केवल

मूर्ति बनाने की कला सिखाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज में एक विचार को जन्म देते हैं।

सबसे बड़ा सवाल गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं देखने में आकर्षक और आसानी से तैयार होने वाली हो सकती हैं, लेकिन उनके विसर्जन के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीओपी पानी में आसानी से प्राकृतिक रूप से नहीं घुलता। इसके साथ ही कई प्रतिमाओं पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक रंग और अन्य सामग्री जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। जब बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जलस्रोतों में होता है तो वहां प्रदूषण का दबाव बढ़ जाता है।

जलस्रोत केवल इंसानों के लिए पानी का माध्यम नहीं हैं। वे असंख्य जलीय जीवों और वनस्पतियों का घर भी हैं। पानी में जाने वाली ऐसी सामग्री जो प्राकृतिक रूप से आसानी से नष्ट नहीं होती, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। रासायनिक रंगों और अन्य गैर-प्राकृतिक पदार्थों से जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इससे मछलियों सहित दूसरे जलीय जीवों के जीवन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए गणेश प्रतिमा की सामग्री का चयन केवल धार्मिक या सौंदर्य का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी विषय बन चुका है। इसके मुकाबले प्राकृतिक मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल विकल्प प्रस्तुत करती है। मिट्टी प्रकृति का हिस्सा है और उचित परिस्थितियों में पानी के संपर्क में आने पर प्राकृतिक रूप से वापस मिट्टी में मिल सकती है। इसका जार्थ यह है कि श्रद्धा से स्थापित की गई प्रतिमा उत्सव के बाद प्रकृति पर लंबे समय तक बोझ नहीं बनती। यही कारण है कि मिट्टी के गणेश की स्थापना को केवल एक फैशन या अभियान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे हमारी धार्मिक परंपरा को प्रकृति के साथ जोड़ने वाली जिम्मेदार पहल के रूप में अपनाने की जरूरत है।

धीरेंद्र शास्त्री की बंगाल यात्रा: नॉन-वेज से शुरू हुई बड़ी बहस

सत्येंद्र प्रताप सिंह

बंगाल में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री सिर्फ एक धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है। हनुमंत कथा के मंच से उनकी अपील ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका असर नवरात्रि से कहीं आगे तक जा सकता है। शास्त्री ने बंगाल के हिंदुओं से अपील की कि नवरात्रि में देवी की प्रतिमाओं के आसपास नॉन-वेज की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सुनने में यह एक धार्मिक अपील है, लेकिन बंगाल जैसे राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील राज्य में इसके मायने कहीं बड़े हैं। क्योंकि यहां सवाल सिर्फ मांसाहार का नहीं है। सवाल है-बंगाल की धार्मिक पहचान कौन तय करेगा?

बंगाल में मछली और मांस का भोजन सदियों से सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है। 'माछ-भात' को बंगाली पहचान से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी तरफ यही बंगाल काली, दुर्गा और शक्ति उपासना की गहरी परंपरा वाला प्रदेश भी है। शाक परंपरा में अलग-अलग क्षेत्रों और मंदिरों में अलग-अलग रीति-रिवाज रहे हैं। इसलिए बंगाल को केवल शाकाहारी या केवल मांसाहारी समाज के चरम से देखना दोनों ही अतिशयोक्ति होगी। यहीं से धीरेंद्र शास्त्री की अपील पर बहस शुरू होती है।

बंगाल की पहचान और खानपान का रिश्ता पुराना है। मछली-भात को अक्सर बंगाली संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। बंगाली साहित्य, सिनेमा और लोकजीवन में भी भोजन को अपनी खास जगह रही है। लेकिन बंगाल की पूरी सामाजिक तस्वीर को केवल मछली-मांस खाने वाली अदी के जरिए समझना अप्रभू होगा।

इसी बंगाल में वैष्णव परंपरा की गहरी जड़ें हैं। बड़ी संख्या में परिवार और समुदाय शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता देते हैं। धार्मिक आस्था, परिवार, क्षेत्र और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर खानपान बदलता रहा है। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी ने एक सीधा सवाल खड़ा किया है-क्या भोजन की पसंद किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान तय कर सकती है?

इस मुद्दे पर बंगाली समाज को एक ही खांचे में रखकर



देखना भी सही नहीं होगा। प्रतिक्रिया के कई स्तर दिखाई दे सकते हैं। एक वर्ग धीरेंद्र शास्त्री की बात को धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखता है। दूसरा वर्ग इसे बंगाल की पारंपरिक खानपान संस्कृति पर टिप्पणी मानता है। वहीं तीसरा वर्ग इसे राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा मानकर देखता है।

यही बंगाल की जटिलता है। यहां किसी व्यक्ति के बंगाली होने का प्रमाण उसकी थाली नहीं है। मछली खाने वाला भी बंगाली है, शाकाहारी भी बंगाली है और अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति भी उतना ही बंगाली है।इसलिए इस बयान के विरोध या समर्थन में पूरे बंगाली समाज की ओर से बोलने का दावा करना खुद बंगाल की विविधता को सीमित करना होगा।

सवाल यहीं से राजनीतिक होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'बंगाली अस्मिता' कोई नया विषय नहीं है। वर्षों से भाषा, संस्कृति, बाहरी-बंगाली की बहस और धार्मिक पहचान चुनावी राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर खानपान को भी सांस्कृतिक पहचान के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका राजनीतिक असर होना स्वाभाविक है।

तृणमूल कांग्रेस के लिए यह मुद्दा बंगाली जीवनशैली और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा के रूप में सामने आ सकता है। भाजपा और तत्पक्ष दक्षिणपंथी राजनीति इसे हिंदू धार्मिक-सांस्कृतिक विमर्श के संदर्भ में रखने की कोशिश कर सकती है। यानी सवाल यह नहीं रह जाएगा कि कौन नॉन-वेज खाता है। सवाल यह बनने लगेगा कि बंगाल की संस्कृति की परिभाषा कौन तय करेगा?

बंगाल की थाली में सिर्फ एक स्वाद नहीं

बंगाल को समझने के लिए उसकी थाली को भी उसी तरह देखना होगा, जैसे उसकी भाषा और परंपराओं को। बंगाल में मछली और मांस की परंपरा है, लेकिन साथ ही शाकाहारी भोजन की भी अपनी जगह है। धार्मिक त्योहारों, पारिवारिक संस्कारों और अलग-अलग समुदायों में भोजन की परंपराएं बदलती रहती हैं।

बंगाल की सांस्कृतिक ताकत इसी विविधता में है। समस्या तब पैदा होती है जब किसी एक खानपान को पूरे समाज की पहचान और दूसरे खानपान को उसकी पहचान के विरोध में खड़ा कर दिया जाए। इससे संस्कृति की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आती, बल्कि राजनीतिक ध्ववीकरण का रास्ता खुलता है।

धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से असहमति जताना पूरी तरह स्वाभाविक है। उसी तरह कोई व्यक्ति उनकी बात से सहमत हो, यह भी लोकातांत्रिक समाज में उसका अधिकार है। लेकिन बहस का स्तर व्यक्ति की पसंद से उठकर विचार और राजनीति तक जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति का नॉन-वेज खाना या न खाना उसकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। इसी तरह किसी धार्मिक व्यक्ति का भोजन को लेकर अपना दृष्टिकोण रखना भी उसका अधिकार है। लेकिन जब वही बात पूरे समाज की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ दी जाती है, तब सवाल ज्यादा गंभीर हो जाता है। बंगाल के संदर्भ में यह संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि यहां संस्कृति और राजनीति का रिश्ता बेहद गहरा है।

दरअसल, यह विवाद भोजन से ज्यादा उस राजनीतिक कथा का हिस्सा बन सकता है जिसमें बंगाल की पहचान को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश हो रही है। एक तरफ बंगाली अस्मिता है, जिसमें भाषा, साहित्य, संगीत, दुर्गापूजा, लोकसंस्कृति और खानपान सब शामिल हैं। दूसरी तरफ धार्मिक पहचान का विमर्श है, जो बंगाल की राजनीति में लगातार ज्यादा मुखर हुआ है। इन दोनों धाराओं के बीच टकराव बढ़ता है तो छोटी-सी सांस्कृतिक टिप्पणी भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।

बिधूना विधानसभा से 2017 में भाजपा तो 2022 में सपा ने दर्ज की जीत

अमन तिवारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। कहीं पुराने गढ़ बचाने की चुनौती है तो कहीं नए राजनीतिक विस्तार की कोशिश। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों के सहारे जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। इसी चुनावी सरगर्मी के बीच, हम आपको उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा सीट के इतिहास, सामाजिक ताने-बाने और उसके राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट की।

उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जिनमें कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इन्हीं में से एक जिला औरैया है। औरैया जिले में कुल तीन विधानसभा सीटें हैं। इनमें- बिधूना, दिबियापुर और औरैया शामिल हैं। सीटों के समीकरण की कड़ी में आज हम औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट की बात करेंगे। औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट पहली बार साल 1957 में अस्तित्व में आई थी और यहां पहला विधानसभा चुनाव 1957 में ही हुआ था।

बता दें कि 1952 में जब देश में पहले आम चुनाव हुए, उस समय बिधूना सीट का स्वरूप वर्तमान से काफी अलग था। 1952 के चुनाव में यह दो-सदस्यीय सीट थी, जिसे %बिधूना पश्चिम-सह-भरथना उत्तर-सह-इटवा उत्तर% के नाम से जाना जाता था। इस चुनाव में कांग्रेस के चासी राम और मेहरबान सिंह विजयी हुए थे। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के सहदेव सिंह और सूवेदार को हराया था।

बिधूना विधानसभा सीट के जातिगत समाकरण और कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां के

विकसित किया गया। इससे अन्य 'इक्कल एरिया' नक्शे महाद्वीपों के सापेक्ष आकार को बिल्कुल सटीक अनुपात में दिखाते हैं।

भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया लेकिन साफ किया कि अगर कोई नया नक्शा बनेगा तो उसमें भारत का पूरा भूभाग सही तरीके से हो, खासकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश भारतीय आधिकारिक नक्शे के मुताबिक हों। इन्हें गलत या भ्रामक दिखाना मंजूर नहीं होगा। मर्केंटर प्रोजेक्शन अभी भी शिक्षा, मीडिया, डिजिटल और सरकारी सामग्री में काफी उपयोग किया जाता है। गोल पृथ्वी को सपाट सतह पर दिखाने की कीमत क्षेत्रफल में विकृति के रूप में चुकानी पड़ती है। यह भूमध्य रेखा से दूर उत्तर और दक्षिण के इलाकों के आकार बिगाड़ देता है। इससे अफ्रीका, लैटिन अमरीका और दक्षिण एशिया के आकार छोटे लगते हैं और दुनिया का नक्शा असंतुलित नजर आता है।

भारत ने पक्ष में वोट के साथ व्याख्या भी दी, जिसमें कहा कि प्रस्ताव बराबर क्षेत्रफल वाले मानचित्रण प्रतिनिधित्व सिद्धांत में बढ़ावा देता है लेकिन किसी खास नक्शे या सीमाओं का समर्थन नहीं करता। प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में एट्रोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान से परहेज किया। भारत ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव का जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के राजनीतिक दर्जे से कोई लेना-देना नहीं है। भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर रुख को स्पष्ट, लगातार एक जैसा और अपराक्राम्य बताया, जो नक्शे में भी हो। अगले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक भारत के रुख को निशाना बनाया और जम्मू-कश्मीर पर अपने पुराने दावे दोहरा दिए, जो न कभी स्वीकार्य थे, न होंगे। निश्चित रूप से नए युग और नए समय के मुताबिक गोल पृथ्वी का नया और सही नक्शा जरूरी है।

सामाजिक ताने-बाने के लिहाज से इस क्षेत्र में क्षत्रिय (ठाकुर) समाज के मतदाताओं की आबादी सबसे अधिक है, जो चुनाव नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। क्षत्रिय समुदाय के बाद इस सीट पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो बेहद निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, ब्राह्मण और अन्य अति पिछड़े व सर्वण समाज के मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं।

1957 में बिधूना विधानसभा सीट पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (एसओसी) के गजेन्द्र सिंह विजयी हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के रघुनाथ सहाय को 7,051 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में गजेन्द्र सिंह को 18,361 वोट मिले, जबकि रघुनाथ सहाय को 11,310 वोट मिले।

2012 के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुए। इन चुनावों में राज्य में भाजपा का बोलबाला रहा, क्योंकि राज्य के चुनावी नतीजों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इसका असर औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट पर भी पड़ा। चुनाव में बिधूना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विनय शाक्य विजयी हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दिनेश कुमार वर्मा को 3,910 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में विनय शाक्य को 81,905 वोट मिले, जबकि दिनेश कुमार वर्मा को 77,995 वोट मिले।

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी (सपा) की रेखा वर्मा विजयी हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रिया शाक्य को 7,765 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में रेखा वर्मा को 92,757 वोट मिले, जबकि रिया शाक्य को 89,492 वोट मिले।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं कृषि, सहकारिता विभाग की योजनाओं की कलेक्टर शर्मा ने की समीक्षा

गरियाबंद। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने जिले में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों, राशनकार्डधारियों, ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एग्रीस्टेक, राइस मिलों सहित अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 371 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनमें 21 दुकानें शहरी क्षेत्र तथा 350 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

जिले में कुल 2 लाख 19 हजार 980 राशनकार्डधारी हैं। कलेक्टर ने सभी छुटे हुए राशनकार्डधारियों का 15 दिवस पर ई-केवाईसी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राशनकार्डों की नियमित जांच कर मृत व्यक्तियों के नाम निगमानुसार हटाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र हितग्राहियों को ही खाद्यान्न का लाभ



मिल सके। कलेक्टर ने पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की। जिले में 14 केन्द्र पहुंचविहीन क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां राशन सामग्री की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए गैस कनेक्शनधारियों की संख्या एवं योजना के लाभ की जानकारी

ली। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 1 लाख 43 हजार 518 गैस कनेक्शनधारी हैं। कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने तथा गैस कनेक्शन के सुरक्षित उपयोग के संबंध में आवश्यक जागरूकता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित राइस मिलों की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में कुल 56 राइस मिल संचालित हैं।

कलेक्टर ने सभी राइस मिलों में आवश्यक व्यवस्थाओं एवं गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा धान के सुरक्षित भंडारण एवं मिलिंग कार्य में निर्धारित मापदंडों का पालन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बारदानों को एकत्रित कर सुरक्षित जगहों पर रखने के निर्देश दिए ताकि धान खरीदी के समय में बारदानों की किसी प्रकार की समस्या न रहे। उन्होंने कृषकों को समय पर खाद एवं उर्वरक उपलब्ध कराने, किसान पंजीयन की प्रक्रिया को सुचारू रखने तथा एग्रीस्टेक से संबंधित कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसानों और हितग्राहियों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने और विभागीय कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

शिक्षक दिवस पर डांस का वीडियो वायरल, गाने के चयन पर उठे सवाल

मुंगेली। शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो मुंगेली के रेम्बो मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल परिसर में विद्यार्थी और शिक्षक फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब कार्यक्रम के स्वरूप और गाने के चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वायरल वीडियो में विद्यार्थी और शिक्षक बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया फिल्मी गाने पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान का है। हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहे कार्यक्रम का पूरा संदर्भ और आयोजन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि शासन-प्रशासन की ओर से लगातार नशामुक्ति और धूम्रपान



विरोधी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में इस तरह के गीत के भी गाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों के बीच भी यह चर्चा है कि स्कूलों में मनोरंजात्मक गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों की उम्र, शैक्षणिक वातावरण और गीत-संगीत के सामाजिक संदेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वायरल वीडियो के बाद अभिभावकों के बीच सवाल है कि स्कूल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक और शिक्षाप्रद संदेश देने वाला भी होना चाहिए।

रेडक्रॉस सोसायटी कबीरधाम की बैठक संपन्न वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा

कवर्धा। कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी श्रीमती तुलिका प्रजापति के मार्गदर्शन में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री नरेंद्र पैकरा ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस कबीरधाम के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में ने जिले में रेडक्रॉस की गतिविधियों की और अधिक प्रभावी बनाने, युवाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, रक्तदान एवं जनजागरूकता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव डॉ. डी.के. ठुंरे ने निर्धारित एजेंडा के अनुसार चर्चा करते हुए वर्षभर संचालित की जाने वाली गतिविधियों की वार्षिक कार्ययोजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष दिवसों पर जनजागरूकता कार्यक्रम, प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करना कार्ययोजना का प्रमुख हिस्सा है। बैठक में लिए गए निर्णयों से जिले में सामाजिक सरोकार, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वैच्छिक रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत एवं युवा सहभागिता की गतिविधियों को और अधिक गति मिलेगी। रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा वर्षभर संचालित की जाने वाली गतिविधियों के माध्यम से जनहित एवं सेवा कार्यों को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में जूनियर रेडक्रॉस एवं यूथ रेडक्रॉस के विद्यार्थियों तथा काउंसलरों के लिए निर्धारित रेडक्रॉस यूनिफॉर्म सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों



में उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित अंशदान राशि इस माह के अंत तक जमा कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रेडक्रॉस सोसायटी का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जिले में प्रतिमाह विभागवार रक्तदान शिविर आयोजित करने हेतु कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि वर्षभर नियमित रूप से रक्तदान गतिविधियों का संचालन किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सहभागिता के अंतर्गत 12 सितंबर को व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही जूनियर एवं यूथ रेडक्रॉस के विद्यार्थियों, वाहन चालकों तथा आम नागरिकों के लिए प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों के अंतर्गत नेपाल बाढ़ राहत के लिए सहयोग जुटाने हेतु जिले में 10 टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमों विकासखंड एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में व्यापारियों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर वित्तीय सहयोग प्राप्त करेंगी।

प्राचार्य को हटाने सड़क पर उतरे छात्र, मूलभूत समस्याएं बताने पर धमकी देने का आरोप

बालोद। शासकीय महाविद्यालय डॉंडीलोहारा में मूलभूत समस्याओं को लेकर छात्र-छात्राओं का आक्रोश सामने आया है। समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर कॉलेज की प्राचार्य रोशन आरा को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बुधवार को दल्लीराजहरा-राजनांदगांव मार्ग पर चक्काजाम किया। प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं ने पहले कॉलेज के सामने दल्लीराजहरा-राजनांदगांव मार्ग पर करीब 10 मिनट तक चक्काजाम किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यार्थियों को सड़क से हटाया। इसके बाद छात्र-छात्राएं कॉलेज के सामने ही धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में व्याप्त मूलभूत



समस्याओं को लेकर जब वे प्राचार्य को अवगत कराते हैं तो उन्हें टीसी काटने की धमकी दी जाती है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और कलेक्टर से भी शिकायत की थी, लेकिन अब तक अपेक्षित निराकरण नहीं हुआ। लगातार प्रदर्शन के चलते कॉलेज परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र-छात्राओं के आंदोलन को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का भी समर्थन मिला है। संगठन के कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ धरने में शामिल हुए और उनकी मांगों के निराकरण की मांग की।

जिला स्तरीय रोजगार मेला का हो रहा आयोजन,167 पदों पर होगी भर्ती

अम्बिकापुर। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, अम्बिकापुर द्वारा शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से 15 सितम्बर 2026, मंगलवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक जिल्बर रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गंगापुर, अम्बिकापुर में आयोजित होगा। रोजगार मेले में

विभिन्न क्षेत्रों के निजी नियोजक शामिल होकर तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदों सहित लगभग 167 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेंगे। सरगुजा संभाग के शिक्षित बेरोजगार युवा इस रोजगार मेले में शामिल होकर अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ई-रोजगार पोर्टल [https://ero-](https://ero-jgar.cg.gov.in/)



jgar.cg.gov.in/ एवं छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर अपना रोजगार पंजीयन तथा रोजगार मेले के लिए पंजीयन, दोनों करना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने

अभी तक ई-रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं कराया है, वे विभागीय पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अपने साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साइज फोटो लाना होगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गंगापुर, अम्बिकापुर में

उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जिला स्तरीय रोजगार मेला पूर्णतः नि:शुल्क है। नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के लिए संबंधित नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे। रोजगार मेले की पूरी प्रक्रिया में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता के रूप में है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

भिलाई में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव

दुर्ग। जिले के भिलाई सेक्टर-2 में एक गटर में नवजात का शव का मिला है. बुधवार को सड़क नंबर 11 और 12 के बीच गटर की सफाई के दौरान करीब 2-3 दिन का नवजात शिशु मिला। गटर जाम होने के कारण स्थानीय लोगों ने बीएसपी प्रबंधन से पानी निकासी की समस्या दूर करने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद गटर की सफाई शुरू कराई गई। इसी दौरान सफाई कर्मचारियों की नजर गटर के अंदर पड़े नवजात पर पड़ी। दरअसल नवजात के मिलने की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। पार्श्व को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद भड़्डी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नवजात को गटर से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है गटर जाम होने से पानी की निकासी प्रभावित थी।। हमें बीएसपी कर्मचारी हैं जैन साहब उन्होंने फोन कर बताया कि यहां एक नवजात का शव मिला है, लग तो ऐसा रहा है कि आसपास के ही किसी परिवार से जुड़ा ये बच्चा होगा।

आबादी से भालू को दूर रखने का प्लान, विभाग ने शुरु की तैयारी

कांकेर। कांकेर में बढ़ता मानव-भालू संघर्ष वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. खासकर कांकेर शहर और आसपास के इलाकों में लगातार भालूओं की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। मरकाटोला में भालू के हमले में दो सगे भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत के बाद वन विभाग अब आबादी वाले इलाकों में विचरण कर रहे भालूओं को रेस्क्यू कर घने जंगलों में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। शहर और बस्तियों के आसपास लंबे समय से घूम रहे भालूओं को पकड़कर ऐसे वन क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा, जहां उनके लिए प्राकृतिक आवास के साथ भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसके लिए नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के घने जंगलों को संभावित स्थान के तौर पर देखा जा रहा है। कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत मरकाटोला में 5 अगस्त को भालू के हमले की भयावह घटना सामने आई थी। हमले में दो सगे भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जिले में मानव-भालू संघर्ष को लेकर वन विभाग की चिंता और बढ़ गई है।

गूगल पे और फोन पे रिसीविंग दिखाकर ठगी

कवर्धा। कबीरधाम जिले के पिपरिया, सासपुर लोहारा और दशरंगपुर में कई लोगों ने फर्जी डिजिटल पेमेंट के बारे में पुलिस में शिकायत की. उन्होंने बताया कि उन्हें पेमेंट की रिसीविंग तो दिखाई जाती थी लेकिन जब खाता चैक किया जाता तो उसमें पैसे नहीं आते थे. इस मामले में अलग-अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में चार एफआईआर दर्ज की गई. 7 सितंबर को ग्राम परसवारा निवासी सूरज पटेल ने पिपरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. बताया कि मोटरसाइकिल से आए एक व्यक्ति ने अपना नाम जेम्स बताया हुए PhonePe के जरिए रकम ट्रांसफर करने के बदले नकद राशि देने की बा कही. आरोपी ने PhonePe स्कैन स्कैन करने के बाद भुगतान की रिसीविंग दिखाई. इसे वास्तविक मानकर सूरज पटेल ने उसे 5 हजार रुपये नकद दे दिए. बाद में बैंक खाता जांचने पर रकम प्राप्त नहीं होने का पता चला. ऐसी ही शिकायत कुछ और लोगों ने की. कि एक व्यक्ति दुकानदारों के पास जाता, उन्हें फोन पे का फर्जी पेमेंट दिखाता है कि हमने आपके खाते में पैसे डाले हैं।

राजमिस्त्री के बेटे बने सीआरपीएफ जवान, क्षेत्र में हर्ष धमतरी।

जिले के मगरलोड ब्लॉक के छोटे से गांव दुधवारा में दो सगे भाईयों का चयन सीआरपीएफ में हुआ था। दोनों भाई ट्रेनिंग पूरी करके गांव वापस लौटे तो ग्रामीणों ने दोनों भाईयों का भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों ने बाइक और तिरंगे के साथ भव्य रैली निकाली। दुधवारा गांव के रहने वाले पवन नेताम और नकुल नेताम ने बचपन से ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का सपना देखा था। आर्थिक परिस्थितियों उनके सामने बड़ी चुनौती थीं, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी अपने सपने से समझौता नहीं किया। दोनों भाई अपने पिता राजा राम नेताम के साथ दूसरे लोगों के मकान बनाने के लिए मिस्त्री का काम करते थे। मजदूरी करने के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फौजी बनने की तैयारी भी करते रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद दोनों भाइयों ने मेहनत जारी रखी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। बड़े भाई पवन नेताम ने दूसरे प्रयास में, जबकि मंझले भाई नकुल नेताम ने पहले ही प्रयास में श्रृङ्खल में चयन हासिल कर लिया।

डायलॉग से जिले के युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मंच’

अम्बिकापुर। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से देश के युवाओं को अपने विचार, नवाचार एवं नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने तथा विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले में भी इस अभियान को अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जागरूकता एवं सहभागिता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मेरा युवा भारत (MY Bharat) के माध्यम से सरगुजा जिले के युवा इस पहल से जुड़कर विकसित भारत के विजन को साकार करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पर आयोजित किज में भाग लेकर अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं तथा आगे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों में नेतृत्व और प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश के टॉप-10 में जिलों में बनाया स्थान

कोरबा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत जारी रैंकिंग में कोरबा टॉप 10 में पहुंच गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के परिणाम जिले के लिए खासे उत्साहजनक रहे हैं। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कोरबा ने 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश के टॉप-10 (10वें स्थान) में अपनी जगह पक्की कर ली है।

अफसर इसे वायु प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए कदम और प्रशासनिक कसावट का नतीजा मान रहे हैं। औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान रखने वाला कोरबा अब स्वच्छ हवा की दौड़ में लगातार मजबूत हो रहा है। कोरबा का नाम अक्सर सर्वाधिक प्रदूषित



स्थानों से जोड़कर देखा जाता था, इस लिहाज से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2026 में कोरबा ने दसवां स्थान हासिल किया है। पहले हम 18वें पायदान पर थे। सर्वेक्षण के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो पॉइंट स्कोर सिस्टम है। उसमें 186 अंक प्राप्त हुआ है- कुणाल दुदावत, कलेक्टर वर्ष 2024 के दौरान इस सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संपूर्ण स्वच्छता पर फोकस रहता है। इस रैंकिंग में भी कोरबा पिछले वर्ष अपनी कैटेगरी में देश का 8वां

सबसे स्वच्छ शहर बना था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में केवल हवा की गुणवत्ता पर फोकस रहता है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें कोरबा नगर पालिका निगम कोरबा को ताजा रैंकिंग में दसवां पायदान मिला है। इन दोनों ही रैंकिंग में कोरबा देश भर के अपनी कैटेगरी वाले शहरों में टॉप 10 में शामिल है।बीते वर्ष कोरबा में सड़कों पर पानी के छिड़काव, हरित क्षेत्रों के विस्तार और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर नकेल कसने की लंबी अवधि की रणनीतियों की नींव रखी गई है। हालांकि इस वर्ष की बारिश के बाद सड़कों की स्थिति काफी खराब है, जबकि वर्तमान रैंकिंग पिछले वर्ष किए गए प्रयासों के आधार पर जारी किए गए हैं। अब आने वाले वर्षों में रैंकिंग सुधार की मजबूत जमीन तैयार की गयी है। ? कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि

जिले के अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से जिला खनिज न्यास के स्वच्छता कंपोनेंट के माध्यम से निरंतर प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहे हैं। वायु की स्वच्छता के लिए बहुत सारे काम चल रहे हैं। वर्तमान में प्लांटेशन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग साढ़े 3 हजार वृक्षों का पौधरोपण खासतौर पर नगर निगम के अंतर्गत किया है। साथ ही साथ नगर निगम में अभी वर्तमान में जो वेस्ट कलेक्शन है और जो रोड की स्वीपिंग है। उसको भी मैकेनिक करने का निर्णय किया गया है, जिसे जिला खनिज न्यास से जिला प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। कलेक्टर ने आगे बताया कि यह प्रक्रिया वर्तमान में टेंडर में है। आने वाले समय में और भी सुधारामक कार्य होंगे, जिससे वायु प्रदूषण और कम होगा। जिले में निरंतर फ्लाई और इसका जो परिवहन होता है।

अमित भंडारी हत्याकांड का एसआईटी ने 7 दिन में किया खुलासा

जांजगीर-चांपा। दो महीने पहले हुए अमित भंडारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी द्वारा गठित एसआईटी ने सीडीआर, नार्को टेस्ट के अलावा डॉंग विमला की मदद से इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफास किया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। अमित भंडारी का संतोषी सिंह से शादी से पहले से प्रेम प्रसंग था। शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी थी। अमित जब भी गांव लौटता था, संतोषी भी अपने पति से विवाद के बाद गांव आ जाती थी। दोनों रात में फोन पर बातचीत करते थे।



पुलिस ने बताया कि घटना वाली रात भी दोनों के बीच करीब 1।30 बजे तक फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद रात करीब 2।30 बजे अमित, संतोषी से मिलने उसके घर के पीछे पहुंचा। इसी दौरान संतोषी का भाई बजरंग सिंह टेंट का काम खत्म कर घर लौटा। घर के पीछे से आवाज सुनकर वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी बहन के साथ अमित को देखा। इसके बाद बजरंग का

अमित से विवाद हो गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान अंधेरे में अमित का सिर पीछे दबाकर से टकराया। अमित जाणे बचाने के लिए दीवार फांदकर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी बजरंग ने पास पड़े छोटे फावड़े से उसके सिर और छाती पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बजरंग घबरा गया।

—> विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम <—

पर्यटन के जरिए नई पहचान गढ़ रहा छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पर्यटन विकास का स्वर्णिम अध्याय

प्राकृतिक संपदाओं, ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक आस्थाओं, जैव विविधता और समृद्ध जनजातीय संस्कृति से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ आज देश के सबसे उभरते हुए पर्यटन राज्यों में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने, निवेश को प्रोत्साहन देने और स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़ने की पहल ने प्रदेश में पर्यटन विकास को नई गति प्रदान की है।



“

मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को सुलभ, समृद्ध और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय गौरव को देश-दुनिया तक पहुंचाया जाए। पर्यटन केवल भ्रमण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि का मजबूत आधार है।

— श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



मधेश्वर पहाड़ बना विश्व रिकॉर्डधारी, छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिली नई पहचान



छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 'लार्जस्ट नेचुरल फैंक्समिली ऑफ शिवलिंग' के रूप में मिली यह मान्यता प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाला क्षण बताया। कुनकुरी ब्लॉक के मयाली गांव के समीप स्थित मधेश्वर पहाड़ प्राकृतिक आस्था का अनूठा केंद्र है। राज्य सरकार के प्रयासों से जशपुर तेजी से पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।



राजधानी रायपुर बना सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का प्रवेश द्वार



राम मंदिर, रायपुर

पुरखौती मुक्तांगन, नया रायपुर

राम मंदिर, मां कौशल्या धाम, ट्राइवल म्युजियम, पुरखौती मुक्तांगन, ऊर्जा पार्क, नंदनवन एवं अन्य प्रमुख स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती दी गई है। धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।



जशपुर की वादियों से उठी चाय की सुगंध, कृषि और पर्यटन को मिली नई उड़ान



छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से जशपुर जिले का सारूडीह चाय बागान आज राज्य की नई पहचान बनकर उभरा है। लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में फैला यह बागान पर्वतों और घने जंगलों के बीच स्थित है, जो पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा दे रहा है। राज्य की पहली चाय प्रसंस्करण इकाई बालाछापर में स्थापित की गई है, जहां काली और हरी चाय का उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्मी कम्पोस्ट आधारित जैविक खेती से तैयार जशपुर की चाय गुणवत्ता और स्वाद के लिए विशेष पहचान बना रही है। चाय बागान ने अनुपयोगी भूमि को हरियाली में बदलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए हैं। आज सारूडीह चाय बागान छत्तीसगढ़ की कृषि नवाचार, ग्रामीण विकास और पर्यटन क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।



सिरपुर और बारनवापारा : विरासत और वन्य पर्यटन का अद्भुत संगम



सिरपुर लक्ष्मण मंदिर

बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

सिरपुर की ऐतिहासिक धरोहर, प्राचीन मंदिर और पुरातात्विक महत्व शोधार्थियों एवं पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बारनवापारा की जंगल सफारी और वन्य जीवन प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय ग्रामीण समुदायों की आय में वृद्धि हो रही है।



मैनपाट : छत्तीसगढ़ का शिमला, प्रकृति और संस्कृति का संगम



मैनपाट अपनी ठंडी जलवायु, हरियाली और तिब्बती संस्कृति के कारण 'छत्तीसगढ़ का शिमला' एवं 'मिनी तिब्बत' कहलाता है। टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, जलजली और उल्टा पानी जैसे आकर्षण इसे विशेष बनाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, रिसॉर्ट विकास और मैनपाट कार्निवल के माध्यम से इसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है।



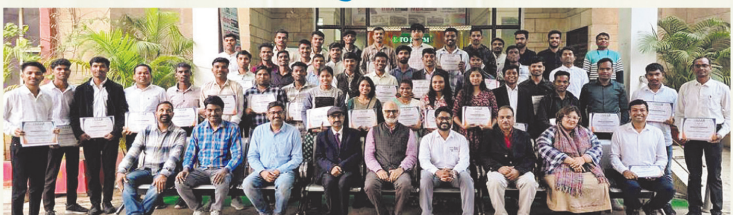
पर्यटन में निवेश का बढ़ता विश्वास



होटल, रिसॉर्ट, वेलनेस सेंटर, इको-रिसॉर्ट और पर्यटन अधोसंरचना में करोड़ों रुपये के निवेश की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। इनसे आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा तथा हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।



पर्यटन क्षेत्र के लिए तैयार हो रही प्रशिक्षित युवा शक्ति



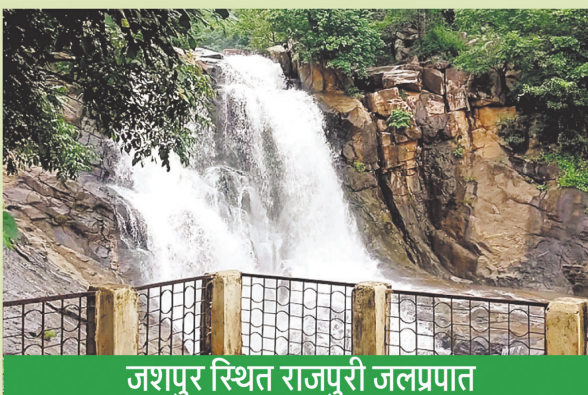
पर्यटन विभाग के सहयोग से सैकड़ों युवाओं को गाइड प्रशिक्षण, संचार कौशल, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, पर्यटक प्रबंधन और आतिथ्य सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित युवा प्रदेश की विरासत को देश-विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



सोनाखान-कसडोल : इको-टूरिज्म विकास का नया मॉडल



नारायणपुर स्थित हांडावाड़ा जलप्रपात



जशपुर स्थित राजपुरी जलप्रपात

शहीद वीर नारायण सिंह की पावन कर्मभूमि सोनाखान और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध कसडोल क्षेत्र को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। घने वन, झरने, जैव विविधता, वन्यजीव और आदिवासी संस्कृति से समृद्ध यह क्षेत्र अब पर्यटन मानचित्र पर से तेजी से उभर रहा है। इको-टूरिज्म से स्थानीय युवाओं को गाइड सेवा, परिवहन, होमस्टे, हस्तशिल्प, खाद्य सेवाओं एवं पर्यटन आधारित उद्यमों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का आदर्श मॉडल भी है।

पर्यटन से बढ़ रहा रोजगार •



मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था •



सशक्त हो रहा ग्रामीण छत्तीसगढ़



प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक विकास का अनूठा संगम आज छत्तीसगढ़ को देश के सबसे संभावनाशील पर्यटन राज्यों में स्थापित कर रहा है। पर्यटन के माध्यम से छत्तीसगढ़ नई पहचान, नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।



भविष्य के छत्तीसगढ़ युवा टाउन प्लानर्स के कंधों पर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

राज्य निर्माण के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में एक साथ 21 सहायक संचालकों की नियुक्ति

रायपुर। शहरों का विकास केवल वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के 21 नवचयनित सहायक संचालकों (योजना) की नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नवचयनित अधिकारियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य निर्माण के बाद पहली बार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में



एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ प्रदेश में तेजी से हो रहे शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री साय ने नवचयनित अधिकारियों के माता-पिता और परिजनों को भी विशेष रूप से बधाई दी। उन्होंने

‘मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गठन को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 17 सहायक संचालकों की नियुक्ति हुई थी, जबकि आज एक साथ 21 युवा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभागों को पर्याप्त मानव संसाधन और प्रोफेशनल क्षमता से सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। गांवों से शहरों की ओर आबादी का विस्तार होने के साथ नगरों की सीमाएं बढ़ रही हैं और प्रमुख सड़कों तथा शहरों के आसपास नई बसाहटें विकसित हो रही हैं।

आने वाले वर्षों में यह गति और तेज होगी। ऐसे में आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक गतिविधियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए दीर्घकालीन एवं वैज्ञानिक योजना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से कहा कि टाउन प्लानिंग केवल नक्शे बनाने या भू-उपयोग तय करने का कार्य नहीं है। इसका सीधा संबंध नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और शहरों के भविष्य से है। एक अच्छी योजना शहर को व्यवस्थित बनाती है, नागरिक सुविधाओं को सुलभ करती है और भविष्य में अनियोजित विस्तार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रोकती है।



भाव को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा, जिसके तहत विभिन्न सेवा गतिविधियों, लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा युवाओं को सेवा और नवाचार से जोड़ने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘सेवा संकल्प अभियान’ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सेवा भाव को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनके अंतर्गत आशीर्वाद का दीया, सेवा चित्र, नमो सेवा गाथा, सेवा स्मरण, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, अवसर पर सेवा गतिविधियां आयोजित करती आ रही है।

17 सितंबर से भाजपा का सेवा संकल्प अभियान

मंत्री चौधरी ने ली प्रभार जिले की वर्चुअल बैठक

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, नेतृत्व एवं समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने और विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र हितराहियों तक पहुंचाने के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

अभियान के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरगुजा, जशपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ तथा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की



प्रशासनिक बैठक ली। उन्होंने अभियान की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, कार्ययोजना, विभागीय दायित्वों एवं प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी ली।

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की यात्रा केवल वर्षों का हिसाब नहीं है, बल्कि यह 25 वर्षों की जनसेवा, नेतृत्व और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास की कहानी है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से इस यात्रा के प्रति जन-आभार व्यक्त करने के साथ विकसित भारत-2047 के संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से

साकार करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सभी कार्यक्रमों का बेहतर विभागीय समन्वय के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान की प्रत्येक गतिविधि ग्राम, वार्ड, विकासखंड एवं जिला स्तर पर अधिकतम जनभागीदारी के साथ आयोजित करना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित समाज के सभी वर्गों को अभियान से जोड़ा जाए। 17 सितंबर की शाम हर घर जलेगा ‘आशीर्वाद का दीया’ अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर की शाम ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम से होगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को दीप प्रज्वलन से जोड़ने की पहल की जाएगी।

समान नागरिक संहिता पर राजनांदगांव में बैठक सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा गठित यूसीसी समिति के नवनियुक्त सदस्यों की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के जिला पंचायत सभाकक्ष में बैठक में यूसीसी समिति के सदस्यों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन पवार एवं सेवानिवृत्त प्राचार्यों डॉ. ज्योति रानी सिंह के समक्ष विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंध जैसे विषयों पर खुलकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

पारंपरिक -सामाजिक मान्यताओं से लेकर आधुनिक वैधानिक सुधारों तक के कई अहम पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ। श्रष्ट के पक्ष और विपक्ष दोनों में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, साहू, कलार, लोधी, यादव, क्रिश्चियन समाज, पटेल, गड़रिया समाज और सेन समाज, अध्यक्ष गोड़ समाज, सामाजिक कार्यकर्ता, उराव समाज, मां बल्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अपने सुझाव समिति के समक्ष रखे।

विभिन्न सामाजिक संगठनों दिए गए सुझाव में समान नागरिक संहिता के तहत सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए।

हड़ताल के ऐलान के बाद बस संचालकों की मंत्री कश्यप के साथ बैठक

रायपुर। किराए में बढ़ोतरी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने 22 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। इस बीच फेडरेशन पदाधिकारियों और बस संचालकों की बुधवार को मंत्री केदार कश्यप के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सहित परिवहन क्षेत्र से जुड़े की विषयों पर चर्चा की गई।

परिवहन मंत्री कश्यप ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई प्रत्येक मांग और व्यावहारिक समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बस संचालकों से समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जाए। यात्रियों को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के



लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

यात्री किराए बढ़ाने की मांग पर जल्द होगा समाधान

बैठक में फेडरेशन ने साधारण यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग रखी। इसके साथ ही 11 मार्च 2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का विषय भी मंत्री के समक्ष रखा गया।

परिवहन मंत्री कश्यप ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यात्री किराए से जुड़े विषय का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी करते हुए इस विषय पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फेडरेशन ने स्लीपर बसों में एक स्लीपर के बदले दो सीटों का टैक्स लेने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त कर एक स्लीपर पर एक सीट के बराबर टैक्स निर्धारित करने की मांग रखी। बस संचालकों ने इस व्यवस्था से होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी भी मंत्री को दी।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

18 से 20 सितंबर तक 14वां इंडिया इंस्टिट्यूल फेयर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 18 से 20 सितंबर तक देशभर के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों, उद्यमियों, निवेशकों और युवाओं की मेजबानी करेगी। साईंस कॉलेज ओपन ग्राउंड में 14वें इंडिया इंस्टिट्यूल फेयर-2026 का आयोजन किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फेयर में प्रदेश के स्वरूख, स्टार्टअप, निर्माताओं, उद्यमियों और युवाओं को देशभर के उद्योगपतियों, खरीदारों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह आयोजन केवल औद्योगिक उत्पादों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, निवेश, रोजगार, तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को एक मंच पर लाने वाला व्यापक औद्योगिक आयोजन होगा। फेयर में उत्पाद एवं तकनीक प्रदर्शनी, B2B मीटिंग, निवेशकों से संवाद, Job Placement Drive, विशेषज्ञों के प्रेरक सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण होंगे। इंडिया इंस्टिट्यूल फेयर के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों की भी उपस्थिति रहेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं प्रमुख विचारक कृष्ण गोपाल की उपस्थिति भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्तर के नीति-निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, उद्यमियों और निवेशकों की मौजूदगी से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मोदी के 25 सालों में किस बात का जश्न मनाने जा रही है: बैज

रायपुर। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष होने पर भाजपा 1 माह तक कार्यक्रम करने जा रही, यह एक राजनैतिक नीटंकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गोधरा कांड से लेकर जेन जी आंदोलन तक का सफर मोदी की 25 सालों की उपलब्धियों में है। मोदी देश के सबसे विफल प्रधानमंत्री साबित हुये हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 12 साल तो देश की जनता को निराश करने वाले रहे हैं। 2014 में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, न 100 दिन में महंगाई कम हुई और न 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार मिला और न ही किसी के खाते में 15 लाख आये। जीएस्टी, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 सालों में उनको और भाजपा को फायदा हुआ है। वे जश्न मनाएं लेकिन देश की जनता को तो मोदी ने निराश किया है। मोदी के 25 साल में छत्तीसगढ़ में 36 लाख दीये जलाने का भाजपा का निर्णय भी छत्तीसगढ़ की जनता के जले पर नमक छिड़कने के जैसा है। मोदी की सरकार ने प्रदेश के लिए किया ही क्या है, केवल छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा को अपने चहेते मित्र को सौंपने के अलावा कुछ भी तो नहीं किया।

छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रचार नहीं, रोजगार चाहिए: शुक्ला

रायपुर। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन शुरू किये जाने के फैसले को युवाओं को ठगाने का नया तरीका बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आज या लिंग का भेदभाव के बिना विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए।

सेवा संकल्प अभियान की रणनीति कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित किया जाएगा। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के माध्यम से सेवा और संवेदना की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। अभियान की तैयारियों और प्रस्तावित गतिविधियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आवास पर छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान अभियान को प्रदेशभर में प्रभावी तरीके से संचालित करने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान कहा गया कि सेवा भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार है। इसी सेवा भाव को जन-जन तक पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य होगा।

साइबर ठगी से महिलाओं और छात्राओं को किया जागरूक

रायपुर। साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से आम नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत रायपुर कमिश्नरेट में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना उरला क्षेत्र के ग्राम गोमची और बेंदरी में महिलाओं एवं छात्राओं को साइबर सुरक्षा की जानकारी दी गई। अभियान के चौथे सप्ताह 6 से 12 सितंबर 2026 के अंतर्गत प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुनीता यादव और थाना स्टाफ ने दोनों गांवों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में महिला समूहों, छात्राओं और स्थानीय महिला समुदाय सहित करीब 250 लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस टीम ने महिलाओं और छात्राओं को व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने, ऑनलाइन उत्पीड़न से बचने और विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने के उपाय बताए। इसके साथ ही सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित तरीके से उपयोग करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। पीडित को तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इसके अलावा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।

कृषि शिक्षा में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को मिला ए ग्रेड

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए छत्तीसगढ़ को गौरवांविक्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा अधिमान्यता बोर्ड ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और उसके अंतर्गत संचालित विभिन्न महाविद्यालयों एवं शिक्षण कार्यक्रमों को अधिमान्यता प्रदान करते हुए ए ग्रेड दिया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि के लिए कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल एवं उनके सभी सहयोगियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है।

चार वर्षों में शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के कारण यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। विदित हो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 2019 में जारी अधिमान्यता सूची में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बी ग्रेड प्राप्त हुआ था। यहाँ यह भी बताना लाजमी होगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विगत वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग में भी 28वां स्थान प्राप्त हुआ था। यह एनआईआरएफ रैंकिंग सूची में स्थान प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है। ए ग्रेड मिलने से विश्वविद्यालय को

होंगे ये लाभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्राप्त होने से अनेक लाभ होंगे। विश्वविद्यालय की साख में वृद्धि होगी। ए ग्रेड मिलने से यह सिद्ध होता है कि विश्वविद्यालय ने शिक्षण, अनुसंधान, अधोसंरचना निर्माण, प्रशासन, छात्र सहायता आदि क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है। नवीन शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को उनके परफार्मेंस अर्थात ग्रेड के आधार पर विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं शिक्षण तथा शोध कार्यक्रमों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज (रजि.) द्वारा समाज के परिवारों की शैक्षणिक, बेरोजगारी, रोजगार, सामाजिक, पारिवारिक, आवश्यकताएं एवं वैवाहिक स्थिति की जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से ऑनलाइन सिक्ख परिवार सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ऑनलाइन परिवार सर्वेक्षण एवं जनगणना फॉर्म की लॉन्चिंग प्रोजेक्टर के माध्यम से मीडिया के सामने की गई जिसमें तक्रर कोड को स्कैन करने के बाद खुलने वाले फॉर्म को दिखाया गया और सिलसिले वार फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया। समाज का मानना है कि किसी भी समाज की मजबूती के लिए यह जानना आवश्यक है कि समाज में कितने परिवार हैं,

समाज को किन क्षेत्रों में विशेष सहयोग और शासकीय योजनाओं की आवश्यकता है इस सर्वेक्षण के बाद उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा परिवारों से संबंधित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से एकत्र की जा रही है। इससे सिक्ख परिवारों को जाकारी देने कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में सर्वेक्षण फॉर्म भर सकेंगे। छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज ने सभी सिक्ख परिवारों से अपील की है कि वे स्वयं अपना सर्वेक्षण फॉर्म भरें तथा अन्य सिक्ख परिवारों को भी फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करें।